



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 1986/कार्तिक 1, 1908

No. 17]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1986/KARTIKA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1986

का. नि. आ. 19(घ)--केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधि-  
नियम, 1957 (1957 का 82) की धारा 184 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए नौसेना (वेतन और भत्ते विनियम, 1968 में और  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--

1. इन विनियमों का नाम नौसेना (वेतन और भत्ते) संशोधन  
विनियम, 1984 है।

2. नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1968 में--

(1) विनियम 4 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित  
रखा जाएगा, अर्थातः--

सारणी

अधिकारियों के प्रवर्ग

परिशिष्ट

(क) सभी शाखाओं के कमांडर (अधिष्ठायी रैंक) तक  
के साधारण सूची आफिसर (इसमें नौसेना विमानन  
और पनडुब्बी शाखाएं सम्मिलित नहीं हैं)।

परिशिष्ट 2

(ख) नौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के  
कमांडर (अधिष्ठायी रैंक) तक के साधारण  
सूची आफिसर।

परिशिष्ट 3

(ग) परिशिष्ट 4

(घ) साधारण सूची (पूर्व शाखा सूची) अधिष्ठायी  
रैंक के आफिसर

परिशिष्ट 5

(ङ) विशेष कर्तव्य सूची आफिसर (इसमें पनडुब्बी  
कांडर के विशेष कर्तव्य सूची आफिसर सम्मिलित  
हैं)

परिशिष्ट 6

(च) मिडशिपमैन

परिशिष्ट 7

(2) विनियम 15 में

(i) उपविनियम (1) में "4(i)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप  
किया जाएगा;

(ii) उप विनियम (2) में "परिशिष्ट 4(ii)" शब्द शब्दों और  
कोष्ठकों के स्थान पर "परिशिष्ट 2 और 3" शब्द और  
शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उप विनियम (4) में, "परिशिष्ट 3 और 4" शब्दों और  
शब्दों के स्थान पर "परिशिष्ट 3" शब्द और शब्द रखे जाएंगे।

(3) विनियम 19 में, उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित  
रखा जाएगा, अर्थातः--

1004 GI/86—1

(1)

“(2) वेतन वृद्धि उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगी जिसमें वह शोध्य हो, चाहे आफिसर कर्तव्य पर हो या छुट्टी पर (जिसमें सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी भी है)”;

(4) विनियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“21 क. कुछ कैदी रिपोर्ट किए गए आफिसर : (i) आफिसर अपनी रैंक (जिसमें संवत्त कार्यकारी रैंक भी है) के उपयुक्त पूर्ण वेतन और भत्ते, बंदी रूप में शब्द से उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन की बाबत समायोजन के अधीन रहते हुए, पाने के हकदार होंगे। यदि पकड़े जाने के पूर्व पूरकता भरता लिया जा रहा था तो वह, भी जारी रहेगा किन्तु ऊँचा स्थान/अस्थायीकरण जल वायु भत्ता संवत्त नहीं किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त के अनुसार अनुज्ञेय वेतन और भत्ते, नौसैनिक वेतन कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले आफिसरों के व्यक्तिगत वेतन लेखाओं में जमा किए जाते रहेंगे। आफिसरों के जमा खाते रकमों में से, प्रदाय भार साधक आफिसर, नौसैनिक वेतन कार्यालय द्वारा, राज्य के व्यय पर, उप विनियम (3) के अनुसार मासिक आर्बिटन भेजे जाएंगे।

(3) आफिसरों द्वारा किए गए कुटुम्ब आर्बिटन, उस अवधि के लिए बेय रहेंगे जिसके लिए वेतन अनुज्ञेय है। यदि कोई कुटुम्ब आर्बिटन नहीं किया जा रहा था तो वेतन और भत्ते के 45% का नया आर्बिटन कुटुम्ब के लिए किया जाएगा।”;

(5) विनियम 23 में, उप विनियम (2) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) आफिसर, जब तट पर हो, तब पोत के भोजन का तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा, सिवाय इसके कि वे वस्तु रूप में निशुल्क राशन या उसके बदले में रुपए लेंगे।

6. विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“25. छुट्टी और अस्थायी कर्तव्य के दौरान अनुज्ञेयता :— छुट्टी पर अनुपस्थिति तथा अस्थायी कर्तव्य की अवधि के दौरान भत्ता, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए उसकी दर पर अनुज्ञेय होगा, जिस पर वह छुट्टी/अस्थायी कर्तव्य पर जाने से पूर्व लिया जा रहा था,

अर्थात्:—

(क) छुट्टी (सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी से विभक्त) के दौरान :—

(i) ऐसे आफिसरों की दशा में जो वार्षिक छुट्टी या वार्षिक छुट्टी के साथ संयोजित फलों या वार्षिक छुट्टी, यदि कोई हो, के साथ संयोजित फलों पर हो, एक बार में चार मास ;

(ii) ऐसे अधिकारियों की दशा में जो क्षमता छुट्टी पर हों, जिसमें उपर उपखंड (i) में उपर्युक्त वार्षिक छुट्टी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, एक बार में चार मास।

स्पष्टीकरण:—I उपर्युक्त खण्ड (ii) में अधिकृत चार मास की परिसीमा, क्षयरोग/कैंसर और अन्य संवे समय तक चलने वाली बीमारियों से पीड़ित किसी आफिसर की दशा में, अन्य सभी बातों में इस विनियमों में अधिकृत भत्तों के अधीन रहते हुए, आठ मास तक बढ़ाई जा सकती है। क्षयरोग/कैंसर और अन्य संवे समय तक चलने वाली बीमारियों से पीड़ित किसी आफिसर की दशा में, आठ मास से अधिक छुट्टी के दौरान भत्ते की संयुक्ती प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा गुणाणु के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

स्पष्टीकरण II:—पहले चार मास से अधिक छुट्टी की अवधि के दौरान भत्ते का संदाय निम्नलिखित प्रमाणपत्र दिए जाने पर ही किया जाएगा, वह या उसका कुटुम्ब या दोनों उस अवधि के दौरान जिसके लिए प्रतिकारत्मक (नगर) भत्ते का दावा किया गया है, उसी स्थान (चाहे वह उसकी ग्रहक सीमाओं के भीतर हो या किसी पारम्वेय क्षेत्र में) पर निवास करते रहे थे जहाँ से वह छुट्टी पर गया था।

(ख) तीन मास से अनधिक अस्थायी कर्तव्य के दौरान।

(ग) यदि छुट्टी अस्थायी कर्तव्य के साथ संयोजित है तो छुट्टी के पहले तीन मास के दौरान।

स्पष्टीकरण:— उपर्युक्त विनियम के प्रयोजनार्थ “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है आफिसर की / का पत्नी/पति, संतान और उसके साथ निवास करने वाले तथा उस पर पूर्णतया निर्भर अन्य व्यक्ति। ऐसा पति/पत्नी/संतान/भाता/पिता जिनकी आय का स्वतंत्र स्रोत है, आफिसर के कुटुम्ब से संबंधित व्यय नहीं समझे जाएंगे, सिवाय तब जब वह सदस्य केवल 100 रुपए प्रतिमास से अनधिक कुल पेंशन (जिसमें पेंशन में अस्थायी वृद्धि और मृत्यु पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान या अन्य सेवानिवृत्ति प्रनुविधाओं के समतुल्य पेंशन भी सम्मिलित है) प्राप्त कर रहा हो।

(7) विनियम 38 से 42 का खोप किया जाएगा ;

(8) विनियम 44 और 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“44. जब भारत से बाहर जाने वाले आफिसर का कुटुम्ब भारत में किसी अस्थायी स्थान को जाता है; ऐसे विवाहित आफिसरों की दशा में जिनके कुटुम्ब विदेश में उनके कर्तव्य के स्थान पर साथ नहीं जाते, और एकल आफिसरों की दशा में, विधन भत्ता उसी दर पर अनुज्ञेय होगा, जिस पर उन्हें स्थानान्तरण भारत के भीतर होने पर स्थानान्तरण उपदान प्राप्त होता।

विधन भत्ते को उपर्युक्त दर पर कोई विनियम प्रतिकर भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

45. जब आफिसर की विदेश में मृत्यु हो जाती है।

ऐसे आफिसर की दशा में जिसकी अपने कुटुम्ब के साथ रहते हुए विदेश में मृत्यु हो जाती है और कुटुम्ब सरकारी व्यय पर भारत लौटता है, मृत आफिसर के कुटुम्ब को विनियम 43 में अधिकृत दर पर विधन भत्ता संवत्त किया जाएगा।”;

(9) विनियम 48 में,—

(i) “गोताखोर प्रतिधारण फीस” शीर्षक के स्थान पर “गोताखोरी भत्ता / प्रतिधारण फीस” शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) “और गहरे गोताखोर” शब्दों के स्थान पर “गहरे गोताखोर और निकासी गोताखोर” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) संघ (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) निकासी गोताखोर आफिसर 150 रुपए प्रति मास

(ii) गहरे गोताखोर आफिसर 150 प्रति मास

(iii) संघ गोताखोर आफिसर 25 रुपए प्रतिमास”

10. विनियम 49 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

## “सारणी

रैंक	नियुक्ति की प्रकृति	भत्ते की दर
1	2	3
(i) रियर एडमिरल	(क) समुद्र पर फ्लैग आफिसर कमांडिंग इंडियन फ्लीट	350 रुपए
(ii) कप्तान	समास्त और समुद्र पोत की स्वतंत्र कमान	200 रुपए
(iii) कमांडर,	समास्त और समुद्र पोत की स्वतंत्र कमान	100 रुपए
लेफ्टिनेंट कमांडर, लैफ्टिनेंट (ख) अन्य		
(i) वॉरिस एडमिरल	फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ आफिसर	300 रुपए
(ii) रियर एडमिरल	फ्लैग आफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट	300 रुपए
(iii) रियर एडमिरल	फ्लैग आफिसर कमांडिंग इस्टर्न फ्लीट	200 रुपए
(iv) रियर एडमिरल	मुख्य कमान धारक फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ कमान धारक नौसेना क्षेत्र	200 रुपए
(v) कमोडोर	कमानधारक कमोडोर भारसाधक नौसेना क्षेत्र	100 रुपए

(II) विनियम 51 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“51 छुट्टी पर अनुपस्थिति, रुग्ण-पूषी रियायत या अस्थायी कर्तव्य के दौरान अनुपस्थिति यह ऐसे स्थायी पदधारियों को अनुपस्थित होगा जो छुट्टी, सस्कार भत्ते रुग्ण-पूषी, रियायत या अस्थायी कर्तव्य के दौरान मर्नोरजम भत्ते के हकदार हैं और जिस तारीख से अर्हक नियुक्ति से उसका नाम काट दिया जाता है उसी तारीख से यह बन्द कर दिया जाएगा।”

12. विनियम 56 में, उपविनियम (i) में, “100 रुपए” अंकों और शब्द के स्थान पर “250 र.” अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

13. विनियम 59 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

## सारणी

रैंक	मासिक दर	
	पूर्व दर	बाकी दर
(i) कैप्टेन / मिहसिपमैन / कार्यकारी 35/—रुपए सब लेफ्टिनेंट / सब लेफ्टिनेंट	17.50र.	17.50र.
(ii) लैफ्टिनेंट और उसके उपर	48/—र.	22.50र.

(14) विनियम 60 में,—

(ii) उपविनियम (ii) के खंड (इ), में “कुरसुरा” के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

निस्तार, बेला, बागीर, बागली और बाघ शीर।”

स्पष्टीकरण:— निस्तार, बेला, बागर, बागली और बाघशीर के आफिसरों और नौसैनिकों को प्रतिरिक्त धन उनके प्रायुक्त होने की तारीख से पूर्ण दरों पर अनुपेय होगा।”

(ii) उपविनियम (i) निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) मिसाईल नौकाएं— प्रतिरिक्त धन, निम्नलिखित मिसाईल नौकाओं पर सेवा का रहे आफिसरों को भी पूर्ण दरों पर देय होगा, अर्थात्:— “विनाश, निर्वात विद्युत, निर्भीक, विजेता, नाशक, बीर, निपात, प्रताप प्रलय, प्रबल, प्रचाण्ड, चपल चमक, चराग, खातक।

स्पष्टीकरण:— इन नौकाओं के आफिसरों और नौसैनिकों को प्रतिरिक्त धन, उनके प्रायुक्त होने की तारीख से अनुपेय होगा —

(iii) उपविनियम (2) में, “सुरंग अपमार्जक” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “कच्छल” शब्द से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) सुरंग अपमार्जनक:

सागर या बेटा सुरंग अपमार्जनक

(ख) भारतीय नौसेना के निम्नलिखित पोत:

“गोदावरी, कुठार, कृपाण, त्रिपूल, तलवार, बड़सपुत्र, व्याम, बेतवा, कृष्णा, कावेरी, शक्ति, मगर, चडियाल, गुलदार, यमुना, इन्स्टी-गेटर, कमोती, कबमत, किलतान, कवरत्ती, कच्छल भरनाला, एंडोथ, अंजली, अंजली, अमीनी, गज, धोरपाड, केसर, शार्दूल, और शरभ, राजपूत, रणजीत और राणा;

(15) विनियम 60 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपस्थान अस्वास्थ्यक जलवायु भत्ता

61. अनुपेयता और दरें: सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषित क्षेत्रों में सेवा कर रहे भारतीय नौसेना के अधिकारियों को उच्च स्थान अस्वास्थ्यक जलवायु भत्ता निम्नलिखित दरों पर और विनियम 156-क के उपविनियम (2) में नौसैनिकों के लिए अधिकृत उम्मीं शर्तों के अधीन रहते हुए अनुपेय होगा।

	रुपए प्रति मास
कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट/सब लेफ्टिनेंट	100/—र.
लैफ्टिनेंट	125/—र.
लेफ्टिनेंट कमांडर	125/—र.
कमांडर और उससे उपर	200/—र.

(16) विनियम 70 में, “1400र. अंकों और अक्षर के स्थान पर जहाँ कहीं भी वे आते हैं, “2400र.” अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(17) विनियम 71 में, “1200” र. अंकों और अक्षर के स्थान पर, “2100र. अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(18) विनियम 76 में,

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— “केन्द्रीय राज्य सरकारों में सिविल पर्वी पर प्रतिनियुक्त आफिसर”

(ii) उपविनियम (i) में, "सिविल नियोजक में आफिसर शब्दों" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय/राज्य सरकारों में सिविल पदों पर प्रतिनियुक्त आफिसर, सिवाय उन आफिसरों के जो आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय में प्रतिनियुक्त है, और जिन्हें प्राप्य यद्यपि सेवा नहीं, सेवा बर्दी पहननी पड़ती है,

(19) विनियम 95 में, उपविनियम (2) में, खंड (ब) में "1800 रु." श्रृंखला और अक्षर के स्थान पर "2000 रु." अक्षर और अक्षर रखे जाएंगे।

(20) उपशीर्ष छद्म गारंटी, उपशीर्ष और विनियम 98 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उद्धान वेतन"

"98" अनुज्ञेयता—विमानन शाखा के ऐसे आफिसर जिन्होंने पायलट (पा) और सर्वेक्षकों (स) के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त की है और पायलटों तथा सर्वेक्षकों के प्रतिकृत काडरों में आते हैं, अपने सामान्य वेतन और भत्तों के अनुरिक्त विनियम 100 में दी गई दरों पर उद्धान वेतन प्राप्त करेंगे। यह पेंशन और उपदान के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा। उद्धान वेतन प्रादाय भारसाधक आफिसर, नौसेना, वेतन कार्यालय, मुम्बई को निम्नलिखित प्रमाणपत्र देने पर अनुज्ञेय होगा :—

टिप्पण 1 : वे आफिसर जो प्रशिक्षण की अवधि के लिए विनियम 54 के अनुसार उद्धान वेतन प्राप्त करते हैं, इन उपबंधों द्वारा शासित होते रहेंगे।

टिप्पण 2 : उद्धान वेतन सेवा-निवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी भ्रम की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा। सेवानिवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी भ्रम के दौरान में उद्धान वेतन लेने के लिए त्रुपर अपेक्षित प्रमाणपत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

उद्धान वेतन प्रमाणपत्र

(31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के अन्त में दिया जाने वाला प्रमाणपत्र)

उद्धान वेतन प्रमाण पत्र

(प्रत्येक मास के अन्त में दिया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि (रैंक) \_\_\_\_\_ (नाम)

\_\_\_\_\_ (वैयक्तिक स)

शाखा \_\_\_\_\_

(क) \*ने उसे दी गई उद्धान सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग किया है और दक्षता का स्वीकार योग्य स्तर बनाए रखा है;

\*\*को उद्धान की कोई सुविधा या अवसर नहीं मिला, किन्तु वह उद्धान कर्तव्य पर वापस आने पर उद्धान करने में प्रसर्थ है;

(ख) ने विनियम 101 में विहित अपेक्षाओं का पालन किया है;

(ग) ने सभी जोखिमों, जिनमें उद्धान करना भी है, के लिए कम-से-कम दो लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से प्राप्त कर लिया है :—

\*जो लागू न हो, उसे काट दें।

(घ) को उद्धान कर्तव्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थायी रूप से प्रायोग्य घोषित नहीं किया गया है

कमान/अफसर वरिष्ठ अफसर

(21) विनियम 99 का जोप किया जाएगा;

(22) विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् "100 रु—(i) आफिसरों का अनुज्ञेय उद्धान वेतन का दर निम्नलिखित है :—

कमान/अफसर और उसके तल्ले	750.00 रुपए प्रतिमास
कप्तान	666.00 रुपए प्रतिमास
रियर एडमिरल और उसके ऊपर	600.00 रुपए प्रतिमास

(2) अनुज्ञेयता और उसकी शर्तें—उपर्युक्त दरों पर उद्धान वेतन इस बात के अधीन रखे हुए अनुज्ञेय होगा कि संबद्ध अधिकारी ने समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से, सभी जोखिमों के लिए, कम-से-कम दो लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो। आफिसर को उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय उत्तरजीविता फायदे सेवा निवृत्ति/निर्मुक्त पर भी देर होंगे।

(23) (i) विनियम 101 के उप विनियम (i) में, (उद्धान बाउंडी, शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ भी वे आते हैं "उद्धान वेतन शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपविनियम (i) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण—समूह बीमा स्कीम के अधीन बीमाकृत राशि और उसके अधीन किया गया अधिवाय 25000 रुपए के स्पूतनम विहित बीमा के लिए और 150 रुपए का औसत मासिक प्रीमियम उद्धान वेतन की बढ़ी हुई दरों की मंजूरी के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।"

(24) विनियम 102 से 104 तक का खोप किया जाएगा;

(25) (i) विनियम 105 क में, उपविनियम (i) के नौवें सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण—इस प्रयोजनाय वेतन विनियम 35 में यथा परिभाषित होगा।

III ख दरें—भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा :—

(क) प्राथमिक कक्षाएं

(कक्षा 1 से 5) ..... 15 रुपए प्रतिमास प्रति बालक

(ख) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं (छठी कक्षा से तीन वर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रक्रम तक) ..... 20 रुपए प्रति मास प्रति बालक

किसी आफिसर को अनुज्ञेय कुल भत्ता एक बार में 60 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

टिप्पण :—प्राथमिक कक्षाओं में किडरगाटन और बिशु कक्षाएं सम्मिलित नहीं हैं।

III ग-शर्तें—भत्ता केवल उन्हीं मामलों में अनुज्ञेय होगा जहाँ कोई व्यक्ति, उस स्थान से, जहाँ वह तैनात है और/या निवास कर रहा है, दूर किसी स्थान पर अपने बालक या बालकों का बिद्यालय भेजने के लिए, निम्नलिखित कारणों से विवश हो :—

(i) उस स्थान पर अपेक्षित स्तर के बिद्यालय या बिद्यालयों का अभाव स्पष्टीकरण-आल-भारतीय बच्चों के लिए भारतीय बिद्यालय के और भारतीय बच्चों के लिए आल भारतीय बिद्यालय का "अपेक्षित स्तर" का नहीं समझा जाएगा। उसी प्रकार, यदि अपनी धार्मिक अवस्था के सिद्धांतों के कारण दूसरी आस्था के निकाय द्वारा चलाए जा रहे किसी बिद्यालय में जाने से कोई बालक निवारित होता है तो समझा जाएगा कि वह बिद्यालय "अपेक्षित स्तर" का नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि उस बिद्यालय में शिक्षण का माध्यम आफिसर को भाषा से भिन्न भाषा है तो भी समझा जाएगा कि वह बिद्यालय "अपेक्षित स्तर" का नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—यदि किसी आफिसर का स्वामन्तरग उस स्थान से, जहाँ अपेक्षित स्तर का कोई बिद्यालय नहीं है, उस स्थान पर हो जाता है, जहाँ ऐसा बिद्यालय है और यदि वह किसी बालक या किन्हीं बालकों के संबंध में पहले स्थान पर भत्ता प्राप्त कर रहा था तो वह, उसके स्वामन्तरग के समय जिस बिद्यालय में उसका/आपका या उसके बालक/ब

रखा या या पढ़ रहे थे, उनके या उनके शैक्षिक वर्ग की समाप्ति तक उन भत्ते के लिए पात्र रहेगा, परन्तु यह तब जब कि बालक उस विद्यालय में उस अवधि तक अध्ययन करता रहे या करते रहें।

## सारणी

रैंक	प्रतिमास रकम
कप्तान	
कमांडर	
सेफ्टिमेंट कमांडर	
सेफ्टिमेंट	550 रुपए
सब-सेफ्टिमेंट	

(ii) उपविनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) उपर्युक्त वर्गों पर पनडुब्बी-वेतन इस बात के अर्धान रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि सम्बद्ध अधिकारी ने समूह बीमा (नौसेना) स्कीम के माध्यम से सभी जोखिमों के लिए कम से कम दो लाख रुपये का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो। अधिकारियों का उक्त बीमा स्कीम के अर्धान अनुज्ञेय उत्तराधिकार फायदे सेवानिवृत्त निर्मुक्त पर भी देय होगा।”

(26) विनियम III, में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) ऐसे कैडेटों का वंश में, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की आय 450-00 रुपए मास के कम है, 55 रुपए प्रतिमास की वित्तीय सहायता;

टिप्पणः—यदि माता-पिता की आय केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त होती है तो कोई वित्तीय सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी;

(27) विनियम III के पश्चात् निम्नलिखित उपसर्ग और विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“बालक शिक्षा भत्ता”

IIIक-पाठ्या-ऐसे आफिसर जिन्होंने कम से कम एक वर्ष सेवा की है और जिसका वेतन 1200 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं है, विनियम IIIख और IIIग में विहित दरों और शर्तों पर बालक शिक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।

स्पष्टीकरण 3.—यदि किसी आफिसर के किसी बालक को, उस स्थान पर जहाँ तैनात हैं और/या नियत कर रहा हो, “अपेक्षित स्तर” के किसी विद्यालय में, रिक्ति न होने से या किसी अन्य कारणवश प्रवेश देने से इन्कार कर दिया जाता है और बालक को उस आफिसर के कर्तव्य और/या निवास के स्थान से दूर किसी विद्यालय में जाने के लिए विवश होना पड़ता है तो आफिसर भत्ते के लिए उसी प्रकार पात्र होगा, मानों उस स्थान पर अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं था।

स्पष्टीकरण 4.—उस स्थान पर जहाँ अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है तो भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम विद्यालय इस प्रकार स्थित है कि बालक या बालकों को विद्यालय के झुलने के समय के लगभग से जाने और विद्यालय बन्द होने के समय के पश्चात्, पर बहुत देर नहीं धापिस लाने के लिए सुविधाजनक रेल या बस सेवा है और एक और की यात्रा में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगता है, जहाँ ये शर्तें पूरी न हों वहाँ उस स्थान से, जहाँ आफिसर तैनात है, वहाँ और/या निवास कर रहा है विद्यालय तक की दूरी किसी भी हो, भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

(ii) फोल्ड स्टेशन पर तैनाती,

(iii) ऐसे नाविक क्षेत्र में तैनाती जहाँ कुटुम्ब के प्रधान के साथ कुटुम्ब का रहना विनिवृष्टतः विवर्जित है।

(3) घ—जहाँ भत्ते के लिए दावा किया जाता है वहाँ एक/विरचनाः का कर्माधिकारियों के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र देना :

(क) तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की अनुपलब्धता, या तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की उपलब्धता किन्तु शैक्षिक प्राधिकारियों से अभिप्राय सूचना के आधार पर वहाँ प्रवेश देने से इन्कार।

(ख) यूनिट को ऐसे फोल्ड/नाविक क्षेत्र में अवस्थिति जहाँ कुटुम्ब के प्रधान के साथ कुटुम्ब का रहना विनिवृष्टतः विवर्जित है।

(28) विनियम 129 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वार्षिक वेतनवृद्धि उस मास की पहली तारीख से अनुज्ञात की जाएगी जिसमें वे देय होती हैं।”

(29) विनियम 131 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

131. क प्रोमोति पर वेतन का नियतन : (1) जब किसी नौसैनिक की प्रोमोति अगले उच्चतर रैंक में हो जाती है तो निचले रैंक में एक वेतनवृद्धि के बराबर एक अभिप्रायत्मक रकम, प्रोमोति की तारीख को उस व्यक्ति द्वारा वर्षों में लिए जा रहे वेतन में जोड़ दी जाएगी और तत्पश्चात् उसका वेतन उच्चतर रैंक के वेतनमान में अगले उच्चतर प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

(2) निम्नतर वेतनमान के अधिकतम पर गतिरुद्ध नौसैनिकों के संबंध में अभिप्रायत्मक वेतन, उपर्युक्त उपविनियम (1) के अधीन अभिप्रायत्मक वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर उच्चतर वेतनमान में वेतन नियत किए जाने से पूर्व निम्नतर वेतनमान में प्रतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम वेतन में जोड़ कर संगणित की जाएगी।

(3) मास्टर चोक पैटी मास्टर 2 वर्ग के रैंक में प्रोमोति पर, चोक पैटी आफिसर के रूप में लिए जा रहे आध्यात्मिक वेतन में सद्व्यवहार वैज वेतन जो जोड़ दिया जाएगा और तत्पश्चात् उपर्युक्त उपविनियमों के अनुसार वेतन नियत किया जाएगा।”

(30) विनियम 132 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : “132 के बुद्धिकैदी रिपोर्ट किए गए नौसैनिक को वेतन और भत्तों को अनुज्ञेयता :

(क) बुद्धिकैदी रिपोर्ट किए गए नौसैनिक—ऐसे नौसैनिक (जिसमें अवैतनिक कमीशन रैंक धारक भी हैं) जो बुद्धिकैदी बना लिए गए हैं, सामान्य वेतन और भत्तों के हकदार होंगे, किन्तु बंद के रूप में शत्रु से प्राप्त होने वाले वेतन को समायोजित किया जाएगा। किसी नौसैनिक (जिसमें अवैतनिक कमीशन रैंक धारक भी हैं) के बुद्धिकैदी के रूप में वेतन और भत्ते तब समाप्त कर लिए जायेंगे जब उसे सेवा से पदच्युत/सिरोम्बुक्त कर दिया जाता है या उसके आचरण के परिणामस्वरूप जिस के कारण शत्रु से उसे बन्दी बना लिया हो या युद्ध बंद के रूप में शत्रु के हाथों में उसके आचरण के उदरिणामस्वरूप उसे कोई और बंद दिया गया हो। ऐसी पदच्युति/सिरोम्बुक्ति/बंद, नौसैनिक के अधिकरण द्वारा विचारण के परिणामस्वरूप, या जोष न्यायालय का कार्यवाहियों या अन्य अवशेषों के आधार पर नौसेना अधिनियम भाग 3 के उपबंधों के अधीन प्रशासनिक रूप से हो सकता है।

स्पष्टीकरण ऊपर निर्दिष्ट पर “वेतन और भत्ते” में विशेष परिभाषा दी गयी है। यदि बन्दी बनाए जाने से पूर्व उच्च स्थायी/अस्थायी रूप

जलवायु भत्ता दिया जा रहा था तो वह बन्द कर दिया जाएगा और नीचे की सारणी में दी गई दरों पर एक विशेष प्रतिकारात्मक भत्ता अनुज्ञेय होगा :—

सारणी

नौसैनिक का रैंक	प्रति मास रकम
प्रवैतनिक कमीशंड आफिसर	34
एम सी पी ओ-1 और II	29
सी पी ओ/पी ओ	22
एल एस	19
एस ई ए-1 एस ई II	17

(ख) कुटुम्ब ग्राबंटन—यदि कौड़ी बनाए जाने से पूर्व से ही कुटुम्ब ग्राबंटन दिए जा रहे थे तो वे दिए जाते रहेंगे। जहाँ ग्राबंटनों का संदाय नहीं किया जा रहा वहाँ नौसैनिक की शुद्धि परिलब्धियों के 60 प्रतिशत तक नए ग्राबंटन दिए जा सकते हैं परन्तु यह तब जबकि :

- (I) वह ग्राबंटिटी (ग्राबंटितियों) का पोषण कर रहा था ;
- (II) ग्राबंटिटी (ग्राबंटितियों) को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और
- (III) संबंधित पोत/स्थापन के कमान आफिसर की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

(31) विनियम 134-क और 134-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“134-क—पात्रता (1) ऐसे सभी नौसैनिक (जिसमें वे भी सम्मिलित हैं, जो कमीशंड आफिसरों के रूप में प्रवैतनिक रैंक धारण कर रहे हैं) जिन्होंने कम से कम एक वर्ष सेवा की है और जिनका वेतन 1200 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं है, पश्चात्कर्ती विनियमों में दी गई दरों और शर्तों पर बालक शिक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी विभाग या कार्यालय में की गई सभी सेवा बालक शिक्षा भत्ते को पात्रता के लिए एक वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजनार्थ हिसाब में ली जाएगी।

(3) सशस्त्र बल/केन्द्रीय सरकार सेवा से सेवानिवृत्ति या सेवान्मूक्ति से पूर्व की गई सेवा, पुनर्नियोजित सैनिक/निवृत्त पेंशन-भोगियों की दशा में उपर्युक्त भत्ते का मंजूरी के लिए एक वर्ष की प्रत्येक अवधि की गणना करने के लिए हिसाब में ली जाएगी, परन्तु यह तब जब कि उनकी पुनर्नियोजित सेवा और उनकी पूर्वतर सेवा निरन्तर है और सेवानिवृत्ति या सेवान्मूक्ति अनुशासनिक आधारों पर या उनके अपने अनुरोध पर नहीं थी।

(4) इस प्रयोजन के लिए वेतन, विनियम 146 में यथा-परिभाषित होगा।

134-ख दरें—भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुज्ञेय होगा :—

(क) प्राथमिक कक्षाएं :—

(कक्षा 1 से 5) ..... 15 रुपए प्रति बालक।

(ख) माध्यमिकता उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं :—(कक्षा 6 से तीन वर्षीय द्विती पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रथम तक) 20 रु. प्रति बालक।

सेना कामिक को किसी एक समय पर अनुज्ञेय कुल भत्ता 60 रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होगा।

टिप्पण :—प्राथमिक कक्षाओं में किबरागैन और शिष्ट कक्षाएं सम्मिलित नहीं हैं।”

(32) विनियम 134-ग के पश्चात् निम्नलिखित भत्ता स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“134-ग(1) तारीख 1-11-73 से बालक शिक्षा भत्ता केवल उन्हीं मामलों में अनुज्ञेय होगा, जहाँ कोई व्यक्ति, उम्र स्थान से जहाँ वह तैनात है और/या निवास कर रहा है, दूर अपने बालक या बालकों को भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसी कारण से विवश है” :—

(क) उस स्थान पर अतिरिक्त स्तर के विद्यालय या विद्यालयों का अभाव।

स्पष्टीकरण 1: आंग्ल भारतीय बच्चों के लिए भारतीय विद्यालय के और भारतीय बच्चों के लिए आंग्ल भारतीय विद्यालय को “अपेक्षित स्तर” का नहीं समझा जाएगा। उसी प्रकार, यदि अपनी आस्था के सिद्धांतों के कारण दूसरी आस्था के निषेध द्वारा बलाए जा रहे किसी विद्यालय में जाने से कोई बालक निवारित होता है तो समझा जाएगा कि वह विद्यालय “अपेक्षित स्तर” का नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि उस विद्यालय में शिक्षण का माध्यम आफिसर की भाषा से भिन्न भाषा है तो भी समझा जाएगा कि वह विद्यालय “अपेक्षित स्तर” का नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: यदि किसी आफिसर का स्थानान्तरण उस स्थान से जहाँ अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है, उस स्थान पर हो जाता है जहाँ ऐसा विद्यालय है और यदि वह किसी बालक या किन्हीं बालकों के संबंध में पहले स्थान पर भत्ता प्राप्त कर रहा था तो वह, उसके स्थानान्तरण के समय जिस विद्यालय में उसका बालक या उसके बालक पढ़ रहा था पढ़ रहे थे, उसके शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक उस भत्ते के लिए पात्र रहेगा परन्तु यह तब जब कि बालक उस विद्यालय में उस अवधि तक अध्ययन करता रहे या करते रहें।

स्पष्टीकरण 3: यदि किसी आफिसर के किसी बालक को, उस स्थान पर जहाँ वह तैनात है और या निवास कर रहा है, “अपेक्षित स्तर” के किसी विद्यालय में, रिक्रिड न होने से या किसी अन्य कारणवश प्रवेश देने से इनकार कर दिया जाता है और बालक काउंस आफिसर के कर्तव्य के और/या निवास के स्थान से दूर किसी विद्यालय में जाने के लिए विवश होता पड़ता है तो आफिसर भत्ते के लिए उसी प्रकार पात्र होगा, मानों उस स्थान पर अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं था।

स्पष्टीकरण 4: उस स्थान पर जहाँ अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है तो भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम विद्यालय इन प्रकार स्थित है कि बालक या बालकों को विद्यालय के खुलने के समय लगभग ले जाने और विद्यालय बन्द होने के समय के पश्चात् पर बहुत दूर से नहीं वापस लाने के लिए मुविधानक रेल या बस सेवा है और एक और को जाना में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगता है। जहाँ ये शर्तें पूर्ण न हों, वहाँ भत्ता, उस स्थान से, जहाँ आफिसर तैनात है और/या निवास कर रहा है विद्यालय की दूरी बाढ़े कितनी भी हो अनुज्ञेय होगा।

(ख) फोल्ड स्टेशन पर तैनाती,

(ग) ऐसे नाविक क्षेत्र में तैनाती जहाँ कुटुम्ब के प्रवास के साथ कुटुम्ब का रहना विनिश्चिततः विवशित है।

(घ) ऐसे वेदों आफिसरों सीडिय नाविकों और नाविका I और II के लिए जो प्राधिकृत विवाहित स्थापन में हैं और जिन्हें क्वाटर के बखर्चे प्रतिकर नहीं दिया जाता है, वे विवाहित आधार से उपलब्धता।

(इ) ऐसे पैटी आफिसरों, सीडिंग नाविक और नाविक I और II के लिए जो प्राधिकृत विवाहित स्थापन में नहीं हैं और जो क्वार्टर के बदले में प्रतिकर मंजूर किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं, विवाहित आवास की उपलब्धता।

(ज) पैटी आफिसरों सीडिंग नाविकों और नाविक I और नाविक II को विवाहित आवास का आइटम जो एक पूर्ण मौखिक वर्ष के लिए नहीं है, परन्तु यह तब जब सरकारी आवास खाली करने पर वह व्यक्ति क्वार्टर के बदले में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) ऐसे बालकों की बायत जिनके लिए 31 अक्टूबर, 1973 को दाखल शिक्षा भत्ता अनुज्ञेय था, विनियम 134-क और के उन पश्चात्कर्षी विनियम में समाविष्ट आदेशों के अनुसार भत्ता पुनरोक्ति करने पर और भले ही उपर्युक्त शर्तों का समाधान न हो तब तक अनुज्ञेय रहेगा जब तक वह वे उसी स्थान या उसी जिले के भीतर पढ़ते रहे वहां वहाँ 31 अक्टूबर, 1973 को अध्ययन कर रहा था या कर रहे थे और उस अवधि तक दिया जाएगा जब तक वे भत्ता मंजूर किए जाने के लिए अन्यथा पात्र थे या हैं।

(iii) उपर्युक्त निबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे सेना कार्मिकों को जो नेपाल सिक्किम और भूटान के नागरिक हैं भारत में विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों के प्रतिरिक्त उन बालकों के संबंध में भी दाखल शिक्षा भत्ता दिया जा सकता है जो उनके देश/राज्य में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(iv) जहाँ बालक शिक्षा भत्ते के लिए दावा किया जाता है वहाँ यूनिट/विरचता का कमान आफिसर दावे के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र भेजेगा :

(क) तैनाती के स्थान पर अर्पित स्तर के विद्यालय की अनु-लक्ष्यता या तैनाती के स्थान पर अर्पित स्तर के विद्यालय की अपलक्ष्यता किन्तु मौखिक प्राधिकारियों से अनिवार्य सूचन के आधार पर वहाँ प्रवेश से इन्कार।

टिप्पणः—सभी पूर्ववर्ती मामलों में कमान आफिसर या विभागाध्यक्ष संबंध मौखिक प्राधिकारियों से सूचना अनिवार्य रूप से प्राप्त होने उपर्युक्त प्रमाणपत्र दे सकता है यदि समय बोन जाने के कारण ऐसी जानकारी एकत्रित करने में कठिनाई है।

(ख) ऐसे फील्ड/नायुक क्षेत्र में यूनिट की अवस्थिति जहाँ कटुम्ब के प्रधान के साथ कटुम्ब का रखा निनिष्ठित विवर्जित है।

(33) विनियम 135-क में "80 प्रतिशत" शब्द के स्थान पर "100 प्रतिशत" शब्द रखा जाएगा।

(34) विनियम 145 में "80% शर्त के स्थान पर "100%" शर्त रखा जाएगा।

(35) विनियम 148 में के उप विनियम (1) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्—

"गृहार्थ : जल या दबाव के भीले नलों के समय के अनुसार पर

फैला	मिटर	पैसे प्रति मिमट
(क) 20 तक	36.58	10
(ख) 20 से 30	36.58 से 54.86	15
(ग) 30 से 40	54.86 से 73.15	20
(घ) 40 से 50	73.15 से 91.44	30
(ङ) 50 से 60	91.44 से 109.73	40
(च) 60 से 75	109.73 से 137.16	55
(छ) 75 से 100	137.16 से 182.88	70

(36) विनियम 148-क के विनियम (1) में विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्—

"सारणी	रुपए प्रतिमास
निकासी गोताखोर प्रथम वर्ग	75
निकासी गोताखोर द्वितीय वर्ग	65
निकासी गोताखोर तृतीय वर्ग,	55

(37) विनियम 149 में उपविनियम (1) में,

मद "(ii) गोताखोर" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

"पौत गोताखोर	75 रु० प्रतिमास
गहरे गोताखोर	98 रु० प्रतिमास"

(38) विनियम 150 के शीर्षक में "परीक्षा" शब्द के स्थान पर "प्रवास" शब्द रखा जाएगा।

(39) शीर्षक "उद्धान बाउटे" और विनियम 151 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्—

"उद्धान वेतन

(151) (वरे) मंगूरोकृत रिक्ति पर कार्य कर रहे वायुकर्मी को, उसकी वायु कर्मिण सेवा की अवधि के दौरान, उसके सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त, प्रतिमास 374 रु. 50 पैसे उद्धान वेतन संबन्ध किया जाएगा। इसे पेंशन और उपदान के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा।

(2) अनुज्ञेयता और उनकी शर्तों संशय निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :-

(क) वायुकर्मी सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि को देय अभिशाय की न्यूनतम अनिवार्य वर के अतिरिक्त विमानन के जोखिमों को समाविष्ट करने वाली भाग्यी बीमा पालिसी/ गारंटीजों (या स्तोय ज वन बीमा निगम या डाक ज वन बीमा निधि) को चलाने के लिए उसके द्वारा संबन्ध प्रीमियमों की मासिक रकम तथा 75 रु. के बीच अस्तर की रकम का सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि में अनिवार्य करना है। ऐसा अतिरिक्त अभिशाय उस मास से अगले मास के वेतन से प्रारम्भ होगा जिसमें वह उदात्त वेतन के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

(ख) वायुकर्मी ने समूह बीमा (गोसेता) स्कीम के माध्यम से सभी जोखिमों के लिए कम से कम एक लाख रु० का अतिरिक्त ज वन-बीमा लाभ प्राप्त कर लिया है। कार्मिकों को उक्त बीमा-स्कीम के अधीन अनुज्ञेय उत्तरज विकास के फायदे सेवानिवृत्ति/निमुक्ति पर भी देय होंगे।

(3) निम्नलिखित प्रमाणपत्र देने पर उद्धान वेतन दिया जाएगा—

उद्धान वेतन प्रमाणपत्र

(31 मार्च, 30 जून, 30 अक्टूबर और 31 दिसम्बर को प्राप्त होने वाली तिमाहियों के घंटे में दिया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि (सेवा सं.) .....  
(रैंक) ..... (नाम) .....  
(ट्रेड) .....

\* (क) ने उसे दी गई उद्धान सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग किया है और प्रवीणता का स्वीकार्य स्तर बनाए रखा है।

\* उसे उद्धान को सुविधा या अवसर प्राप्त नहीं था किन्तु उद्धान कार्मिकों पर वापिस जाने पर वह उद्धान करने में समर्थ है।

\* जो कार्मिक न हों उसे काट दे।

(ख) ने प्रत्येक बल कायिक भविष्य निधि/अनिवार्य बीमा सुरक्षा में न्यूनतम अतिरिक्त अभिदाय से संबंधित शर्तें पूरी कर व, है।

(ग) को उद्धान कर्तव्यों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया।

कमान आफिसर/वरिष्ठ आफिसर

टिप्पण 2: उद्धान-वेतन सेवानिवृत्ति पर्यंत छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा।

सेवानिवृत्ति पर्यंत छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश के दौरान में उद्धान वेतन लेने के लिए ऊपर अपेक्षित प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

उद्धान-वेतन प्रमाण-पत्र

(31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के अंत में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र)

(40) विनियम 152 के उपविनियम (2) में,

"100 रु." श्रृंखला और अक्षरों के स्थान पर "250 रु." श्रृंखला और अक्षर रखे जाएंगे।

(41) विनियम 154 के उप विनियम (2) में, "2 रुपये" श्रृंखला और अक्षर के स्थान पर "7 रुपये" श्रृंखला और अक्षर रखे जाएंगे।

(42) विनियम 155 में,

(1) उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अतिरिक्त धन उन नौसैनिकों को, जिनमें से भी हैं जो रिक्काड़े पाइपों के हैं, विनियम 58 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और विनियम 60 में अधिकारित जलधाराओं के वर्गीकरण के अनुसार, पूर्ण या आधी दर पर देय होगा।";

(ii) उपविनियम (2) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सारणी

नौसैनिक	मासिक धरें	
	पूर्ण दर	आधी दर
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	35.00	17.50
मुख्य पैटी आफिसर	35.00	17.50
पैटी आफिसर	30.00	15.00
मुख्य नाविक	30.00	15.00
नाविक I और II	25.00	12.50
वरिष्ठ (बॉय)	20.00	10.00"

(43) विनियम 156 के पर्याप्त निम्नलिखित शीर्षक और विनियम अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उच्च स्थाय/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता

156क अनुज्ञेयता और धरें—सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित क्षेत्रों में सेवा कर रहे नौसैनिकों की उच्च/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ता निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय होगा:

प्रतिमास रूप

मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	90
मुख्य पैटी आफिसर	
पैटी आफिसर	70
मुख्य नाविक	
नाविक I और II	50

(2) यह भत्ता उस तारीख से अनुज्ञेय होगा जिसको उस क्षेत्र में किसी यूनिट/विरचना में तैनात किए जाने पर कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पहुंचता है; यह उस तारीख के समाप्ति हो जाएगा जिसके वह उस क्षेत्र के छोड़ता है।

अपवाद: ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में अधिकतम 14 दिन तक उसक्षेत्र से अनुपस्थित रहा हो भत्ता प्राप्त करता रहेगा परन्तु यह तब तक जब वह उस क्षेत्र में लौट आता है जिसमें भत्ता अनुज्ञेय है:

(i) जब वह रुग्ण व्यक्तियों की सूची में हो;

(ii) जब वह आकस्मिक छुट्टी पर हो;

(iii) जब वह अस्थायी कर्तव्य पर हो;

स्पष्टीकरण 1: भत्ता ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जो अत्यंत कोई पद धारण कर रहे हों और विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अस्थायी कर्तव्य पर जाएं। तथापि, भत्ता ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञेय होगा जो अत्यंत पद धारण कर रहे हों और 14 दिन से अधिक की निरंतर अवधि के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी यूनिट आदि से संबंध और ऐसा कोई वैदिक भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो अस्थायी कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण 2: ऐसे व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में टुकड़ियों में सेवा कर रहे हैं, भत्ते की अनुज्ञेयता के प्रयोजनार्थ तैनात समझे जाएंगे यदि टुकड़ियां उस क्षेत्र में 14 दिन से अधिक की निरंतरता अवधि तक अल्प नियोजित की जाती हैं। इसके विपरीत, ऐसे यूनिटों/विरचनाओं के, जो परिभाषित क्षेत्र में स्थित हैं, व्यक्ति, जो टुकड़ियों के साथ उस क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं भत्ते के पात्र नहीं रहेंगे यदि टुकड़ियां 14 दिन से अधिक की निरंतर अवधि के लिए उस क्षेत्र से बाहर रहती हैं।

स्पष्टीकरण 3: वार्षिक छुट्टी रुग्णता या आकस्मिक छुट्टी से भिन्न किसी अन्य छुट्टी पर क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति को भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 4: एक वर्षिक क्षेत्र से दूसरे को अंतराल के दौरान भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(3) रियायती क्षेत्र के लिए अनुज्ञेय विशेष प्रतिकारक भत्ता, इस भत्ते के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा।

(44) विनियम 162 में, खंड (ख) के पदवाच निम्नलिखित अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) ऐसे बाह्य स्थानों पर (i) 30 दिन तक कमांडर राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैप्टेन कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय में उपस्थित रहने के दौरान

जब सरकार राजन को (ii) 30 दिन के पदवाच निदेशक आपूर्ति नहीं कर सकती। राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य"



(45) विनियम 172-ख के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“समुद्री कर्तव्य भत्ता”

172-ग-अनुज्ञेयता और दर : यह भत्ता पोत पर सेवा कर रहे सभी नाविकों को जिनमें अस्थायी कर्तव्य पर लगाए गए व्यक्ति भी हैं उन व्यक्तियों के दौरान अनुज्ञेय होगा जब उनके पोत बेम पतन से मर्यादा में दूर हों

रैंक	प्रतिमास रूपए
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	53
मुख्य पैटी आफिसर	
पैटी आफिसर	38
मुख्य नाविक	33
नाविक I और II	30”;

(46) विनियम 174 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सारणी

प्रवर्ग	प्रतिवर्ष रूपए
प्रथम वर्ग सर्वेक्षण मास्टर मुख्य पैटी आफिसर वर्ग I और II	700
अभिलेखक मुख्य पैटी आफिसर	600
पैटी आफिसर और उससे नीचे	500
द्वितीय वर्ग सर्वेक्षणों अभिलेखक	400
तृतीय वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक	300

(47) विनियम 176 में, उपविनियम (1) में, सारणी में मुख्य पैटी आफिसर से संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“रेटिंग	दैनिक दर	मासिक सीमा
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	2 रूपए	अधिकणित नहीं है।

(48) (1) विनियम 176-क में, उपविनियम (1) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“मारणी

रैंक	प्रतिमास रूपए
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर I और II	350 रूपए
सीफ पैटी आफिसर	300 रूपए
पैटी आफिसर	275 रूपए
मुख्य नाविक	265 रूपए
नाविक I और II	250 रूपए”

(II) उपविनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) उपर्युक्त दरों पर पनबुद्धी वेतन इस बात के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा कि संबंध कामिक ने रासूद बीमा (नौसेना) स्काम के माध्यम से, सभी जोखिमों के लिए कम-से-कम एक लाख रूपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो। कामिक को उक्त बीमा स्काम के अर्धम अनुज्ञेय उत्तराधिकार के फायदे सेवा निर्भुक्ति पर भी देय होंगे।

1004 GI/86—2

(49) विनियम 176-क के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“176-ख आशुलिपि भत्ता—(क) एक लीडिंग राइटर राइटर को तब जब वह कप्तान द्वारा समायोजित पोतों में या स्काइन के सीडरों में आशुलिपिक के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हों, (ख) एक मुख्य पैटी आफिसर राइटर/पैटी आफिसर राइटर को जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग, भारतीय बेटा के कर्मचारीवृन्द में हो और आशुलिपिक के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हों निम्नलिखित शर्तों पर, 30 रूपए प्रतिमास की दर से आशुलिपिक भत्ता अनुज्ञेय होगा :

(i) यह भत्ता केवल तभी संदत्त किया जाएगा जब उस व्यक्ति को अर्हित आशुलिपिक निर्णित किया गया हो और वह विहित व्यवसाय परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले।

(ii) भत्ता केवल तभी अनुज्ञेय होगा जब व्यक्ति पोत पर सेवा रहा हो और सिविल कर्मचारीवृन्द उपलब्ध न हों।

(50) विनियम 177-क के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“नाराज/निरोध अधिनिर्णीत नाविकों के कुटुम्बों को निर्वाह भत्ता

177-ख-अनुज्ञेयता और दर : ऐसे विवाहित नाविकों के कुटुम्ब को, जिनके लिए कमान आफिसर या सेना न्यायालय द्वारा नाराजाम या निरोध अधिनिर्णीत किया जाता है किन्तु जिन्हें सेवा से परच्युत नहीं किया जाता है, 60 रूपए प्रतिमास निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। भत्ता उस अवधि के दौरान देय होगा जिसमें वेतन और भत्ते समपद्धत कर लिए जाते हैं। भत्ते को ऐसे व्यक्तियों को बाद में परिहार या दोषमुक्ति के रूप में उपलब्ध होने वाले किन्हीं पावनों मद्धे समायोजित किया जाएगा।

टिप्पण : जब उपर्युक्त रकम मनीभाईर से भेजी जाती है तो मनीभाईर का कमीशन सरकार पर प्रभारित किया जाएगा।”

(51) विनियम 178-क के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बोनस

178-ख बोनस की अनुज्ञेयता-प्रत्येक नाविक के व्यक्तिगत बालू लेखा खाता में, प्रत्येक तिमाही के अन्त में लेखा खाता में विद्यमान जमा खाते प्रतिगेष की, उसमें से तिमाहियों के अंतिम मास के शुद्ध वेतन और भत्ते छोड़कर, 50 रूपए की प्रत्येक पूर्ण राशि पर 43.75 रूपए की दर से बोनस जमा किया जाएगा। बकाया में 50 रूपए से कम की राशियों को छोड़ दिया जाएगा।

उन व्यक्तियों की वशा में, जिनकी मृत्यु हो जाती है, बोनस उस तिमाही के पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम दिन तक जमा किया जाएगा जिसमें उनके खाते अंतिम रूप से बंद किये जाते हैं।

उस बोनस पर कोई आयकर प्रभारित नहीं किया जाएगा।”;

(52) विनियम 191 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“191 पश्चात् अगस्त, 1947 के पश्चात् दिए गए श्रुता अलंकरण-  
वर और शर्तें (1) किसी आफिसर या नाविक को दिए गए श्रुता अलं-  
करणों से संलग्न मासिक विशेष पेंशन की दरें निम्नलिखित होंगी :—

श्रुता पारितोषिक	प्रतिमास पेंशन
	रुपए
(क) (1) परम वीर चक्र	100.00
(2) परमवीर चक्र की प्रत्येक पट्टी	40.00
(ख) (1) महावीर चक्र	75.00
(2) महावीर चक्र की प्रत्येक पट्टी	25.00
(ग) (1) वीर चक्र	50.00
(2) वीर चक्र की प्रत्येक पट्टी	20.00
(घ) (1) अग्रोह चक्र	90.00
(2) अग्रोह चक्र की प्रत्येक पट्टी	35.00
(ङ) (1) कीर्ति चक्र	65.00
(2) कीर्ति चक्र की प्रत्येक पट्टी	20.00
(च) (1) शौर्य चक्र	40.00
(2) शौर्य चक्र की प्रत्येक पट्टी	16.00

उक्त दरें 1 जनवरी, 1972 से प्रभावी होंगी और 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् दिए गए सभी पारितोषिकों को लागू होंगी।

(2) पेंशन उस कार्य/घटना की तारीख से अनुज्ञेय होगी जिसकी बाबत अलंकरण प्रदान किया गया है।

(3) एक समय में केवल एक अलंकरण (और उसकी एक या अधिक पट्टियों के लिए) पेंशन ली जाएगी और उच्चतर अलंकरणों के प्रदान किए जाने की तारीख से पेंशन की वह दर छोड़ दी जाएगी जो कम अनुकूल है।

(4) पेंशन अलंकरण प्राप्त करने वाले की मृत्यु तक अनुज्ञेय होगी, और उसकी मृत्यु पर उसकी ऐसी विधवा को, जिसके साथ उसका विधि-पूर्ण विवाह विधिमार्ग्य संस्कार से हुआ था, अनुज्ञेय होगी, और वह अपने पुनर्विवाह या मृत्यु पर्यंत पेंशन प्राप्त करती रहेगी ;

परन्तु यदि विधवा अपने स्वर्गीय पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और मृतक के ऐसे अन्य जीवित उत्तराधिकारियों के साथ निवास करती रहती है जो कुटुम्ब पेंशन के पात्र हैं तो उसे ऐसा संशय किया जाता रहेगा।

स्पष्टीकरण:—साधारणतया, किसी आफिसर/नाविक को देय पेंशन उसकी मृत्यु पर उस विधवा को मिलेगी जो उनको पहले पत्नी थी। किन्तु केन्द्रीय सरकार को विशेष संज्ञा से, ऐसे पेंशन को प्राप्तिकर्ता की, यदि पेंशन उस विधवा को जो प्राप्तिकर्ता की पहली पत्नी थी, इसमें इसके पूर्व उपस्थित के अनुसार देय नहीं रहती तो सभी विधवाओं के बीच बराबर बांटा जा सकता है और सभी विधवाओं को पेंशन संशय समाप्त हो जाएगा।

(5) यदि किसी अविवाहित पुरुष को मरणोपरान्त पारितोषिक दिया जाए तो मौद्रिक भत्ता उसके पिता या माता को दिया जाएगा और यदि मरणोपरान्त पारितोषिक पाने वाला विधुर हो तो भत्ता 18 वर्ष से कम के यथास्थिति उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को संदत्त किया जाएगा।

(6) निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धोप ठहराए जाने पर इस विनियम के अधीन पेंशन समपहृत करनी जाएगी और भारत के राजपत्र में पारितोषिक का समपहृत अधिसूचित किए जाने की तारीख से बंद कर दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) देशद्रोह

(ख) राजद्रोह

(ग) विद्रोह

(घ) कायरता

(ङ) संघर्ष के दौरान अभिमुखता

(च) हत्या

(छ) डकैती

(ज) बलात्कार

(झ) अप्राकृतिक अपराध

समपहृत पेंशन पारितोषिक के भारो के राजपत्र में यथा अधिसूचित प्रकाशित पर संदेय हो जाएगी ;

(53) विनियम 209 और 210 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“209 आफिसरों की बाबत प्रतिकर (1) यदि किसी आफिसर की वैयक्तिक सम्पत्ति, जैसे उपस्कर, वस्त्र (जिसमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं) पुस्तकें, यंत्र औजार या उपसाधन नीचे वर्णित परिस्थितियों में गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं तो सरकार उस आफिसर को प्रतिकर देने के लिए दायी होगी परन्तु यह तब जब कि वह हानि, क्षति या नाश दायेदार की उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है।

(1) जब हानि, क्षति या नाश, किसी शत्रु या विप्लव कारियों की कार्रवाई से हुआ हो ;

(2) जब हानि, क्षति या नाश तब किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो जब वह व्यक्ति कर्तव्य पर, सड़क, नदी, रेल, समुद्र, वायु मार्ग से यात्रा कर रहा हो ;

(3) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश किसी नौसैनिक पोत सरकारी भवन में, या सरकार के स्वामित्व में हो या किसी भयंकर भाड़े पर हो, या समुचित प्राधिकार के अधीन और किसी मान्यताप्राप्त सेवा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी टैंक में हुआ हो, परन्तु यह तब जब उस आफिसर के पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उस आवास में रहने के प्रतिरक्त कोई विकल्प न हो ;

(4) जब रेल, सड़क, वायुमार्ग नदी या समुद्र मार्ग से यात्रा में वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश हो जाता है परन्तु यह तब जब वे उस समय सरकार के प्रभावधीन और अभिरक्षा में थे ;

(5) जब वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन नष्ट की जाती हों,

(6) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश कर्तव्यों के निर्वहन के के दौरान होता है।

2. प्रतिकर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा संयोजित जांच बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर संजूर किया जाएगा। ऐसी मदों की बाबत जो आफिसरों द्वारा सज्जा भत्ते में से कट की जाती अशुद्ध है, इस बात का निर्धारण जांच बोर्ड करेगा कि नष्ट हो गई मद की लागत और कमीशन किए जाने के समय दिए गए प्रारम्भिक सज्जा भत्ते में से कट की गई सभी मदों की कुल लागत के बीच का अनुपात क्या है और प्रतिकर प्रारम्भिक सज्जा भत्ते के उसी अनुपात तक सीमित होगा।

3. ऐसे उपस्कर, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं, जो मुक्त की जाती हैं, जांच बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बचते में दी जाएगी।

4. वस्तुओं (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं), उपस्कर और वस्तुओं की ऊपर वर्णित परिस्थितियों में होने वाली हानि के लिए प्रतिकर जांच बोर्ड द्वारा सिफारिश दिए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है किन्तु यह प्रत्येक अलग-अलग मामले में 1000/- रुपये तक सीमित होगा। आभूषणों, प्रणीतकों, वातानुकूलकों तथा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की रकम का निर्धारण करते समय वस्तुओं का लागत मूल्य उपयोग की अवधि और उनके अवक्षयण को भी संगणना में लेगा। यदि जांच बोर्ड उपर्युक्त रकम से अधिक प्रतिकर की सिफारिश करता है तो मामला गुणावगुण के आधार पर विचारण के लिए सरकार को निवेष्ट किया जा सकता है।

210. नाविकों की दशा में प्रतिकर (1) यदि नाविक की वैयक्तिक संपत्ति, जैसे, उपस्कर, वस्त्र (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं), पुस्तकें, यंत्र, औजार, या उपसाधन नौसे वर्णित परिस्थितियों में गुप्त, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते हैं तो सरकार उस नाविक को प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगी परन्तु यह तब जब कि वह हानि, क्षति या नाश, वायेदार की उपाय के कारण नहीं हुआ है।

- (i) जब हानि, क्षति या नाश, किसी शत्रु या विप्लवकारियों कार्रवाई से हुआ हो;
- (ii) जब हानि, क्षति या नाश तब किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो जब वह व्यक्ति, कर्तव्य पर, सड़क, नदी, रेल, समुद्र या वायु मार्ग से यात्रा कर रहा हो;
- (iii) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश किसी नौसैनिक पोत या सरकारी भवन में जो सरकार के स्वामित्व में हो या किराए अधुवा भाड़े पर हो, या समुचित प्राधिकार के अधीन और किसी मान्यताप्राप्त सेवा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी टैंक में, हुआ हो परन्तु यह तब जब उस व्यक्ति के पास अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उस आवास में रहने के प्रतिरिक्त कोई विकल्प न हो;
- (iv) जब रेल, सड़क, वायुमार्ग, नदी या समुद्र मार्ग से यात्रा में वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश हो जाता है परन्तु यह तब जब वे उस समय सरकार के प्रभाराधीन और अभिरक्षा में थीं;
- (v) जब वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन नष्ट की जाती हैं;
- (vi) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान होता है;

(2) प्रतिकर, जांच बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाएगा।

वैयक्तिक वस्तुओं की बायत अधिकतम सीमा "अवकाश दर" होगी।

(3) ऐसे उपस्कर, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं जो मृत्यु की जाती हैं, जांच बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बदले में दी जाएंगी।

(4) वस्तुओं (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं), उपस्कर और वस्तुओं की ऊपर वर्णित परिस्थितियों में होने वाली हानि के लिए प्रतिकर, जांच बोर्ड द्वारा सिफारिश किए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है किन्तु हर प्रत्येक अलग-अलग मामले में 500 रुपये तक सीमित होगी। आभूषणों, प्रणीतकों, वातानुकूलकों तथा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की रकम का निर्धारण करते समय वस्तुओं का लागत मूल्य, उपयोग की अवधि और उनके अवक्षयण को भी संगणना में लेगा। सिविल वस्तुओं की दशा में प्रतिकर सिविल वस्त्र भत्ते तक निर्बंधित होगा। यदि जांच बोर्ड उपर्युक्त रकम से अधिक प्रतिकर की सिफारिश करता है तो मामला गुणावगुण के आधार पर विचारण के लिए सरकार को निवेष्ट किया जा सकता है।

54. उक्त विनियमों के विनियम 220 में निम्न रूप में संशोधन किया जाएगा :—

उपर्युक्त विनियमन की पंक्ति 2 में आने वाले शब्द "प्रतिकर" के परवात् "उपरोक्त विनियमों के विनियम 209 और 210 अधीन हैं", शब्द अस्तित्ववर्तित किए जाएंगे।

(55) विनियम 246 के स्वात पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"246. सीमाशुल्क के संशय के लिए, अधिम —ऐसे आक्रियों के जो विदेश में नियमित पद धार कर रहे हैं और वे जिन्हें विदेशी सरकारों की प्रतिनिधित्व पर भेजा जाता है, जिनकी कार्यविधि एक वर्ष या अधिक है, जो विनियम 245 के अधीन मोटर कार के लिए अधिम लेने के हकदार हैं, केन्द्रीय सरकार, विदेश में क्रय की गई और उनके द्वारा स्थानांतरण पर भारत में लाई जा रही कारों पर सीमाशुल्क देने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए अधिम मंजूर कर सकती है। ऐसे अधिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, भारत सरकार है।

टिप्पण. सीमा शुल्क के संशय के लिए मंजूर किए गए अधिम पर कोई व्याज प्रभाव नहीं होगा।

(2) भारत में सीमाशुल्क के संशय के लिए अधिम को प्रत्येक अधिम माना जाएगा और उसे मोटर कार के क्रय के लिए पढ़ने से मंजूर अधिम यदि कोई है, के साथ आधेतिवित्त नहीं किया जाएगा।

(3) सीमाशुल्क के संशय के लिए अधिम को रकम 12000 रुपये या बान्धव में संदेय सीमाशुल्क होगी। यदि किसी आक्रिय ने मोटर कार के क्रय के लिए पढ़ने हो उधार लिया है और वह पूर्णतः प्रतिपंरत नहीं है तो सीमाशुल्क उधार और मोटर कार-उधार का बकाया मिलाकर 14000 रुपये या 14 मास का वेतन (100 रुपये प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले आक्रियों की दशा में 17 मास का वेतन) दोनों में से जो भी कम हो, उपरोक्त अधिक नहीं होगा।

टिप्पण. सीमाशुल्क के संशय के लिए मंजूर किए गए अधिम की रकम, किसी भी दशा में, वास्तव में संदेय सीमाशुल्क से अधिक नहीं होगी।

(4) सीमाशुल्क—अधिम की रकम, संबंध आक्रियों को जो सीमाशुल्क के संशय के लिए तत्पश्चात् प्रतिनृति की जाने वाली रकम मय समायोजित की जाएगी। यदि अधिम की मूल रकम, प्रत्यक्ष आदेशों के अनुसार, प्रतिनृति की गई रकम मध्ये पूर्णतया समायोजित नहीं की जा सकती है तो बकाया रकम, उस मास से, जिसमें सीमाशुल्क की प्रतिनृति की जानी है, अगले मास से संबंध आक्रिय के वेतन से एकमुस्त बसूल की जाएगी।

(5) ऐसे आक्रिय की दशा में जो सेवानिवृत्त होने वाला है, बसूली इस प्रकार विनियमित की जाएगी कि सेवानिवृत्त से पूर्व उस आक्रिय को अंतिम वेतन देने के समय तक अधिम का बकाया पूर्णतया बसूल हो जाए।

(6) सीमाशुल्क के संशय के लिए अधिम विदेश भेजे जाने वाले उन आक्रियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जो विनियम 245 के अधीन मोटर कार के लिए अधिम के हकदार नहीं हैं, अर्थात् वे जिन्हें विदेश अस्थायी कर्तव्य पर प्रतिनृति पर भेजा जाता है।

(7) मोटर कार के क्रय के लिए अधिम की मंजूरी के लिए विहित ग्रन्थ में सीमाशुल्क के संशय के लिए अधिम की दशा में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(8) निम्नलिखित उधारों के लिए निष्पादित किए जाने वाले बंधक पत्र के प्ररूप परिशिष्ट 11-ग और 11-ख में अधिकृत है :—

(क) जब मोटरकार के क़य या सीमाशुल्क के संदाय के लिए केवल एक अग्रिम मंजूर किया जाता है या जब दोनों प्रयोजनों के लिए केवल एक अग्रिम मंजूर किया जाता है;—परिशिष्ट 11-ग और,

(ख) जहां सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम पूर्वतर अग्रिम से मोटरकार क़य किए जाने के पश्चात् मंजूर किया जाता है—परिशिष्ट 11-घ 1”;

(56) विनियम 248 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“248-क-अतिरिक्त शर्तें—उन मामलों में जहां आफिसर विनियम 246 के अधीन उधार लेने के हकदार हैं किन्तु विदेश में क़य करके भारत में लार्ई गई कारों पर, जिन पर साधारणतया आयात अनुश्रुति अनुज्ञेय है, सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं हैं, उधार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए :—

(क) सीमाशुल्क के संदाय के लिए उधार की रकम 12000 रुपए या वास्तव में संदेय सीमाशुल्क तक निर्बन्धित होगी। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क उधार तथा कार के क़य के लिए उससे पूर्व लिए गए, किन्तु प्रतिसंदर्भ नहीं किए गए उधार, यदि कोई है, की बाबत बकाया अनिशेष, कुल मिलाकर 14000 रुपए या 14 मास के बेतन (1000 रुपए प्रतिमास से कम बेतन ले रहे आफिसर की वशा में 17 मास के बेतन) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) इस अग्रिम की मंजूरी की सीमाशुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए तर्क के रूप में दिया जाएगा और दावा सर्वथा सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किए गए आदेशों से शासित होगा।

(ग) आफिसर को तब तक कार का विक्रय करने के लिए अनुश्रुत नहीं किया जाएगा जब तक अग्रिम का संदाय नहीं हो जाता।

(घ) मिशन के प्रधान और रक्षा मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होगा कि विदेश में तैनाती के देश या देशों में सरकारी सेवक द्वारा कार रखना लोकहित में आवश्यक था और भारत में उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए भी आवश्यक होगा।

(ङ) अग्रिम की कोई रकम और व्याज के परादेय रहते तक कार को पूर्णतः बीमाकृत रखा जाएगा, जिसमें व्यक्तियों द्वारा बलबा और सिविल अशांति की बाबत बीमा भी सम्मिलित है।

(च) भारत में सीमाशुल्क के संदाय के लिए अग्रिम को पृथक अग्रिम, माना जाएगा और उसे मोटरकार के क़य के लिए पहले से मंजूरीकृत अग्रिम यदि कोई है, के साथ आमेसित नहीं किया जाएगा।

(छ) सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किया गया अग्रिम अधिक से अधिक साठ किस्तों में बसूली होगा। सीमाशुल्क अग्रिम की बसूली को, मोटरकार के क़य के लिए मंजूर किए गए पूर्वतर अग्रिम, यदि कोई हो, की बकाया बसूलियों से संबद्ध नहीं किया जाएगा। पूर्वतर अग्रिम मद्दे बसूलियों, इस अग्रिम की मंजूरी के पश्चात् भी, मंजूरी के निबंधनों के अनुसार की जाएगी।

(ज) नियुक्त होने वाले आफिसर की वशा में सीमाशुल्क अग्रिम की बसूली, किस्तों की रकम बढ़ाकर इस प्रकार विनियमित की जाएगी कि सेवानियुक्ति से पूर्व आफिसर द्वारा अंतिम बेतन लेने से पूर्व ही यह अग्रिम और उस पर व्याज की पूर्ण बसूली हो जाए।

(झ) स्थायीवस्तु या अस्थायी आफिसर की वशा में, उधार मंजूर करने से पूर्व तुलनीय या उच्चतर प्रास्थिति के किसी स्थायी केन्द्रीय सरकारी सेवक से प्रतिभूतिभूति अभिप्राप्त की जानी चाहिए।

(ञ) उधार मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार होगी। मोटरकार के क़य के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए विहित अन्य शर्तें इस अग्रिम के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

(ट) ये आदेश ऐसे आफिसरों को लागू नहीं होंगे जो विदेश में नियमित पद धारण नहीं कर रहे हैं, अर्थात् वे जिन्हें विदेश में अस्थायी कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र के संगठनों और उनके विभिन्न अधिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए आफिसर उधार की मंजूरी के हकदार होंगे।

(ठ) उधार पर उसी दर से व्याज लगेगा जो मोटरकार के प्रयोजन के लिए उधार को लागू है 1”;

(57) विनियम 248 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“248 मंजूरी देने वाला प्राधिकारी—(1) वे आफिसर जिन्हें मोटर साइकिल क़य करने के लिए उधार अनुज्ञेय है और वे प्राधिकारी जो उन्हें मंजूर करने के लिए सक्षम हैं, नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

किसे अनुज्ञेय है

मंजूरी देने वाला प्राधिकारी

(क) नौसेना मुख्यालय में सेवा करने वाले (नौसेनाध्यक्ष से भिन्न) सभी नौसैनिक आफिसर।

नीनेनाडवज।

यथास्थिति

(ख) नौसैनिक मुख्यालयों से बाहर नौसैनिक लटीय स्थापनों में सेवा करने वाले सभी नौसैनिक आफिसर।

(1) पलैंग आफिसर कमांडिंग इन चोक, पश्चिमो, नौसेना कमान, मुंबई।

(2) पलैंग आफिसर कमांडिंग इन चोक, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम।

(3) पलैंग आफिसर, कमांडिंग ब्रिगेड नौसेना क्षेत्र, कोकोन। यथास्थिति

(ग) जल पर की नियुक्तियों पर सेवा करने वाले नौसैनिक आफिसर

(1) पलैंग आफिसर कमांडिंग इन चोक, पश्चिमो नौसेना कमान, मुंबई।

(2) पलैंग आफिसर कमांडिंग इन चोक, पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम।

(3) पलैंग आफिसर, कमांडिंग ब्रिगेड नौसेना क्षेत्र, कोकोन।

- (घ) इंस्ट्रक्शनल स्टाफ एंड स्टुडेंट्स आफि- कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कालेज, सर रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंगटन। नई दिल्ली।
- (ङ) कर्मेचारिबन्ध और विद्यार्थी आफिसर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा सेवा कालेज, जिन्हें वेतन रक्षा प्राक्कलनों, राष्ट्रीय नई दिल्ली। रक्षा कालेज, नई दिल्ली से दिया जाता है।

(2) अग्रिम 3500 रुपए या वनमान के वेतन या मास्य पारिश्रम के पूर्वानुमानित मूल्य तक, जो भी सब से कम हो, सीमित होगा”;

(58) विनियम 253 में, विद्यमान खंड (क) से

(च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- (क) भारसाधक नौसेना आफिसर उमके अग्रिम सेवा कर रहे कामियों की दशा में।
- (ख) कमांडिंग आफिसर, तटीय स्थापन। उसके अग्रिम सेवा कर रहे कामियों की दशा में।
- (ग) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई कमान, मंबई।
- (घ) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, बिशाखापत्तनम।
- (ङ) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, परिवर्तमान।
- (च) फ्लैग आफिसर कमांडिंग, पूर्वी।
- (ज) फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, अग्नि नौसेना कमान, कोच्चन।

59. विनियम 257ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“257ख—महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर अग्रिम वेतन

(1) पात्रता—नियमित नियुक्ति में सेवा कर रहे नौपैतिकों, परिवारों (बाँपों) और शिशुओं को, जिनका वेतन 600/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है, महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर निम्नलिखित विशेषताओं और शर्तों के अधीन रहते हुए अग्रिम वेतन मंजूर किया जा सकता है :—

(क) अग्रिम की रकम 200 रुपए या एक मास का वेतन (जिनमें नियुक्ति वेतन, मर्यादण वेतन और कार्यकारी भत्ता भी है), इनमें से जो भी कम हो, होगी।

(ख) अग्रिम संबंधित उत्सवों से पूर्व लिया जाता चाहिए। यह केवल उन्हीं को अनुज्ञेय होगा, जो कर्तव्य पर हों और अग्रिम लेने के समय जिनके वैयक्तिक खालू खाता लेखा में कोई ऋणी प्रतिशेष न हों।

(ग) अग्रिम अधिक से अधिक बस बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। पहली वसूली अगले मास के नियमित संदाय के प्रारंभ होगी। प्रत्येक किस्त की रकम निकटतम रुपए तक पूर्णांकित की जाएगी और प्रतिशेष इतिहास किस्त में वसूल किया जाएगा।

(घ) अग्रिम, एक कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार अनुज्ञेय होगा। पोर्तों और स्थापनाओं के कमान आफिसर, उत्सव के स्थानीय महत्व पर विचार करने के पश्चात् ऐसे उत्सवों के अवसर नियत करेंगे जिन पर अग्रिम अनुज्ञात किया जाएगा।

(ङ) दूसरा उत्सव अग्रिम केवल तब ही मंजूर किया जाएगा जब किसी पूर्व अवसर पर मंजूर किया गया उत्सव अग्रिम पूर्णतः वसूल किया जा चुका हो।

(च) यदि कोई उत्सव, एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार पड़ता है तो अग्रिम केवल एक अवसर पर अनुज्ञेय होगा।

(2) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी—पोत/स्थापन का कमान आफिसर ऐसे अवसरों पर अग्रिम वेतन मंजूर करने के लिए प्राधिकृत है। वह ऐसे नौपैतिकों को, जो नियमित नियुक्ति पर सेवा नहीं कर रहे हैं पर जिन्होंने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तथा जिनका अग्रिम के समा-योजन तक सेवा में बना रहना संभाव्य है, ऐसा अग्रिम अपने विवेकानुसार मंजूर कर सकता है।

स्पष्टीकरण—गणतंत्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस अग्रिम वेतन के प्रयोजन के लिए उत्सव के अवसर माने जा सकेंगे।”;

(60) विनियम 266 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अवैतनिक सब-लेफ्टिनेंट	1000/- रुपए प्रतिमास
अवैतनिक लेफ्टिनेंट	1100/- रुपए प्रतिमास

(61) विनियम 269 में, अंक “720” के स्थान पर अंक “1440” रखे जाएंगे ;

(62) विनियम 272 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“समुद्री कर्तव्य भत्ता

273. अनुज्ञेयता और दरें—समुद्री कर्तव्य भत्ता जन पर सेवा कर रहे सभी अवैतनिक आयुक्त आफिसरों को, जिनमें अस्थायी कर्तव्य पर संलग्न आफिसर भी हैं उन अवधियों के दौरान अनुज्ञेय होगा जब उनके पोत बेस परतनों से यथायथे दूर हों।”;

“उच्च स्थान/प्रस्थाप्यकर जलवायु भत्ता

274. अनुज्ञेयता और दरें—अवैतनिक आयुक्त आफिसर, विनियम 156क में यथा अधिकृत नौपैतिकों को लागू शर्तों के अधीन 90 रुपए प्रतिमास की दर से उच्च स्थान/प्रस्थाप्यकर जलवायु भत्ते के हकदार होंगे।”;

(63) परिशिष्ट 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

## “परिशिष्ट—2

सभी शाखाओं के साधारण सूची आफिसरों (जिसमें नौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखाएं नहीं हैं) के लिए वेतन की दरें  
(विनियम 4 देखिए)

सेवा का वर्ष	कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	सबलेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	लेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	लेफ्टिनेंट कमाण्डर रु. प्रतिमास	कार्यकारी कमाण्डर रु. प्रतिमास	कमाण्डर रु. प्रतिमास
1.	750	—	—	—	—	—
2.		830	—	—	—	—
3.		870	—	—	—	—
4.			1100	—	—	—
5.			1150	—	—	—
6.			1200	—	—	—
7.			1250	—	—	—
8.			1300	—	—	—
9.			1350	—	—	—
10.			1400	1450	—	—
11.			1450	1500	—	—
12.				1550	1750	—
13.				1600	1750	—
14.				1650	1750	—
15.				1700	1750	—
16.				1700	1750	—
17.				1750	1800	1800
18.				1800	1850	1850
19.				1800	1900	1900
20.				1800	1950	1950
21.				1800	1950	1950
22.				1800	1950	1950
23.				1800	1950	1950
24.				1800	1950	1950
काल वेतनमान कमाण्डर कप्तान रियर एडमिरल बाइस एडमिरल नौसेना अध्यक्ष	1900 रु. प्रतिमास 1950-75-2100-100-2400 रु. 2500-125-2-2750 रु. 3000 रु. प्रतिमास 4000 रु. प्रतिमास			कार्यकारी या अधिष्ठायी		

टिप्पण—1. कमाण्डर के वेतन की दरें वे होंगी जिनके लिए वे कप्तान के रूप में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार हकदार हैं।

टिप्पण—2. ऐसे आफिसर जिन्हें कर्नल वेतनमान के अनुसार कमाण्डर की रैंक में अधिष्ठाया जावे प्रोवेंस किया गया हो और जो प्राविष्टन नियुक्तियों पर धृत नहीं हैं, 1900 रु. प्रतिमास नियत वेतन लेंगे तथापि ऐसे आफिसरों को जब कमाण्डर (चयनित) द्वारा कार्य रिक्तियों में स्थान-पन्न रूप से, एक बार में छह मास से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे परवात्पूर्वी पद के लिए अनुमेय वेतन लेंगे।

टिप्पण—3. विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के आफिसरों से भिन्न ऐसे आफिसरों को जिन्हें लेफ्टिनेंट कमाण्डर का उच्च वेतन वाला कार्यकला रैंक दिया गया हो, निम्नलिखित वेतन प्राप्त करेंगे:—

सेवा का 8वां वर्ष पूर्ण होने तक — 1350 रुपये  
सेवा का 9वां वर्ष पूर्ण होने तक — 1400 रुपये

## परिशिष्ट-3

नौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के साधारण सूची आफिसरों के वेतन की दरें  
(विनियम 4 देखिये)

सेवा का वर्ष	कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट रु. प्रतिमास	सब लेफ्टिनेंट रु० प्रतिमास	लेफ्टिनेंट रु० प्रतिमास	लेफ्टिनेंट कमाण्डर रु. प्रतिमास	कार्यकारी कमाण्डर रु. प्रतिमास	कमाण्डर रु. प्रतिमास
1.	825					
2.		910				
3.		950				
4.			1200			
5.			1250			
6.			1300			
7.			1350			
8.			1400	1450		
9.			1450	1500		
10.			1500	1550		
11.			1550	1600	1750	
12.				1650	1800	1800
13.				1700	1850	1850
14.				1700	1900	1900
15.				1750	1950	1950
16.				1800	1950	1950
17.				1800	1950	1950
18.				1800	1950	1950
19.				1800		
20.				1800		
21.				1800		
22.				1800		
23.				1800		
24.				1800		
काल वेतनमान कमाण्डर	1900 रु. प्रतिमास					
कप्तान	1950-75-2100-100-2400 रुपये	} कार्यकारी या अधिष्ठायी				
रियर एयरमिरल	2500-125-2-2750 रु.					
वाइस एडमिरल	3000 रु. प्रतिमास					
नौसेना अध्यक्ष	4000 रु. प्रतिमास					

टिप्पण—1 कमांडर के वेतन की दरें वे होंगी जिनके लिए वे कप्तान के रूप में अपनी उद्येयता के अनुसार हकदार हैं।

टिप्पण—2 ऐसे अधिकारी जिन्हें काल वेतनमान के अनुसार कमाण्डर की रैंक में अधिष्ठायी रूप में प्रोन्नत किया गया हो और जो प्राधिकृत नियुक्तियों पर धृत नहीं हैं, 1800 रुपये प्रतिमास नियत वेतन लेंगे किन्तु ऐसे आफिसरों को जब कमाण्डर (चयनित) द्वारा रिक्तियों में स्थापनापन्न रूप से, एक बार में छह मास से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे पश्चात्पूर्व पद के लिए अनुश्रेय वेतन लेंगे।

टिप्पण—3 विमानन और पनडुब्बी शाखाओं के ऐसे आफिसरों को जिन्हें लेफ्टिनेंट कमाण्डर का उच्च वेतन वाला कार्यकारी रैंक दिया गया हो, निम्नलिखित वेतन प्राप्त करेंगे :—

सेवा का सातवां वर्ष पूर्ण होने पर—1400 रु. प्रतिमास” ;

(64) परिशिष्ट 4 का लोप किया जाएगा;

(65) परिशिष्ट 5, 6 और 7 का प्रतिस्थापन

परिशिष्ट 5, 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

## "परिशिष्ट 5

अधिव्यापी रैंक के साधारण सूची (शाखा बाह्य सूची) आफिसरों के लिए वेतन की दरें  
(नियम 4 देखिए)

लेफ्टिनेंट कमांडर	र. प्रतिमास
प्रोमोति पर	1550
1 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1600
2 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1650
3 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1700
4 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1700
5 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1750
6 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
7 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
8 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
9 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
10 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
11 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
12 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1800
कमाण्डर	
प्रोमोति पर	1850
1 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1900
2 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1950
3 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1950
4 वर्ष की सेवा के पश्चात्	1950
टिप्पण—कार्यकारी कमांडर 1800 र. प्रतिमास के नियत वेतन का हकदार होगा।	
कप्तान	कप्तान साधारण सूची की तरह

## परिशिष्ट—6

विशेष कर्तव्य सूची आफिसरों (इसमें पनडुब्बी कांडर के विशेष कर्तव्य सूची आफिसर भी हैं) के लिए वेतन की दरें  
(नियम 4 देखिए)

विशेष कर्तव्य सूची	र. प्रतिमास
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य) (परिवीक्षाधीन)	750
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट [अस्थायी/सब लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)]	830-40-950
लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)	1100-50-1500
लेफ्टिनेंट कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1550-50-1700-50-1800
कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1800-50-1950
विशेष कर्तव्य सूची—पनडुब्बी कांडर	
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य) (परिवीक्षाधीन)	825
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट (अस्थायी/सबलेफ्टिनेंट) (विशेष कर्तव्य)	910-40-1030
लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य)	1200-50-1550
लेफ्टिनेंट कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1650-50-1700-50-1800
कमांडर (विशेष कर्तव्य)	1800-50-1950



## परिशिष्ट—7

मिडिलेरीयन मूल वेतन

(नियम 4 देखिए)

मिडिलेरीयन मूल वेतन ..... 560 रु. प्रतिमास;  
 सेप्टेन्ट (विशेष कर्तव्य)

68. परिशिष्ट 9 का प्रतिस्थापन—परिशिष्ट 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट, 9 ,,

नौसैनिक के लिए वेतन की दर  
 (नियम 125 देखिए)

ग्रुप “क”

साक्षात् : सभी परिसिस्पी और मैकेनिसियन

शिक्ष/परिसिस्पी	मैकेनिसियन	रु. प्रतिमास
शिक्ष पहला वर्ष		195
शिक्ष दूसरा वर्ष		200
शिक्ष तीसरा वर्ष		205
शिक्ष चौथा वर्ष		210
परिसिस्पी 5 वर्ष		240-6-248
कार्यकारी परिसिस्पी		300-8-308
परिसिस्पी 4 वर्ष	मैकेनिसियन 4 वर्ष	340-8-358
परिसिस्पी 3 वर्ष	मैकेनिसियन 3 वर्ष	391-10-441
परिसिस्पी 2 वर्ष	मैकेनिसियन 2 वर्ष	435-10-485
परिसिस्पी 1 वर्ष	मैकेनिसियन 1 वर्ष	500-10-550
मुख्य परिसिस्पी	मुख्य मैकेनिसियन	565-15-640
मास्टर मुख्य पैटी		620-20-740
फ़ाफ़िसर-2		
मास्टर मुख्य पैटी		725-25-825
फ़ाफ़िसर-1		

ग्रुप “ब” (गैर परिसिस्पी)

रैंक	रु. प्रतिमास
नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन	215
नौसैनिक—2	230-6-42
नौसैनिक—1	240-6-312
मुख्य नौसैनिक	250-6-310-8-328
पैटी फ़ाफ़िसर	300-8-380
मुख्य पैटी फ़ाफ़िसर	385-15-475
मास्टर मुख्य पैटी फ़ाफ़िसर-2	470-20-600
मास्टर मुख्य पैटी फ़ाफ़िसर-1	600-25-700

टिप्पणी—निम्नलिखित में से कोई भी विशेष अर्हता अर्जित कर लेने पर, चिकित्सा सहायकों को वेतन के प्रयोजनार्थ ग्रुप “ग” से नौसैनिक विमानन नौसैनिकों के उत्संख्यी प्रवर्गों को अनुसूची वेतन की दरों में अर्जित कर दिया जाएगा ।

विशेषज्ञ कर्तृता पाठ्यक्रमों के नाम	वर्ग
1. उन्नत परिचर्या	1 और 2
2. चिकित्सीय स्टोर	1 और 2
3. प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीकी	1 और 2
4. शल्य क्रियागृह तकनीकी	1 और 2
5. रेडियोग्राफी (एक्सरे) सहायक और/या तकनीकी	1 और 2
6. विशेष रोग	1 और 2
7. भौतिक चिकित्सा	1 और 2
8. स्वास्थ्य विज्ञान	1 और 2
9. मनोविकार विज्ञान परिचर्या	1 और 2
10. वंत शल्य क्रिया गृह सहायक	1 और 2
11. रक्तदान सहायक	1 और 2
12. औषध वितरक	1 और 2
13. वन्त तकनीकी और/या वन्त स्वास्थ्य विज्ञानी	1 और 2 ।"
ग्रुप "ग" (गैर-परिशिष्टी)	
रैंक	रु. प्रतिमास
नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन	200
नौसैनिक-2	210-5-280
नौसैनिक-1	220-5-280
मुख्य नौसैनिक	235-6-295-8-311
पैटी आफिसर	300-8-380
मुख्य पैटी आफिसर	385-15-475
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर-2	480-20-600
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर-1	600-25-700

## नौसेना विमानन नौसैनिक

रैंक	रु. प्रतिमास
नौसैनिक प्रशिक्षणाधीन	245
नौसैनिक 2	255-6-267
नौसैनिक 1	285-7-369
मुख्य नौसैनिक	310-7-380-8-396
पैटी आफिसर	360-8-440
मुख्य पैटी आफिसर	455-15-545
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 2	550-20-670
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 1	650-25-750

टिप्पण: वायुयान यांत्रिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नियमित वायुयान यांत्रिक वर्ग 4 में प्रोन्नति किए गए पैटी आफिसर एयर फ़िटर/पैटी आफिसर एयर आयुद्ध फ़िटर, वायुयान यांत्रिक के रूप में वेतन के स्तर पर पहुंचने तक विद्यमान वेतनमान में ही वेतन प्राप्त करना रहेगा।

## पनडुब्बी ग्रंग के गैर परिशिष्टी नौसैनिक

रैंक	रु. प्रतिमास
नाविक प्रशिक्षणाधीन	245
नाविक 2	255-6-267
नाविक 1	285-7-369
मुख्य नाविक	310-7-380-8-396
पैटी आफिसर	360-8-440
मुख्य पैटी आफिसर	455-15-545
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 2	550-20-670
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर 1	650-25-750

टिप्पण:—पनडुब्बी ग्रंग के परिशिष्टी/मैकेनिशियन नौसैनिक वेतन की ग्रुप "क" व "ख" में लेंगे।

## परिवार (बाँय)

	रु. प्रतिमास
प्रत्यावेदन पर,	55.00
प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर	58.00
समव्रगामी परिवार	80.00

साधारण टिप्पण—ऊपर उपर्युक्त वेतनमान के प्रतिरिक्त, विद्यमान दरों पर और विद्यमान शर्तों पर "संसाधारण क्षेत्र वेतन भी अनुज्ञेय होगा";

(67) परिशिष्ट II-ग में-(i) शीर्षक के नीचे

"[विनियम 239(4) और 243 देखिए]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर [विनियम 239(4), 243 और 246 देखिए]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण—सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए अधिम पर क्योंकि कोई व्याज प्रसार्य नहीं है अतः करार प्ररूप में प्रयुक्त व्याज पत्र इन उधार को लागू नहीं होगा।";

68. "परिशिष्ट II-घ" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परिशिष्ट II-घ

पृष्ठक पूर्वतर अधिम से त्रय की गई मोटर गाड़ी पर सीमाशुल्क के संदाय के लिए अधिम के लिए बंधपत्र का प्ररूप (विनियम 246 देखिए)

एक पक्षकार के रूप में थी-----और

-----का पुत्र है (जिसे इसमें प्रागे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उसके उत्तराधिकारी और समनुवैशित भी हैं अब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें प्रागे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उनके उत्तरवर्ती और समनुवैशित भी हैं) जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच प्राज तारीख-----को किया गया प्रतिरिक्त भार का विलेख।

उधार लेने वाले ने तारीख-----के बंधक विलेख (जिसे इसमें प्रागे "मूल विलेख" कहा गया है) द्वारा उसकी अनुसूची में उल्लिखित मोटरगाड़ी खरीदने के लिए -----रु. के अधिम को और विलेख में दी गई दर से व्याज को प्रतिभूत करने के लिए विलेख में दी गई शर्तों पर मोटरगाड़ी सरकार को आग्रमान रख दी है।

उधार लेने वाले को सरकार द्वारा अधिम दिए गए-----रूप की उक्त रकम में से, मूल विलेख के निबन्धनों के अनुसार मूलधन मद्धे -----रूप की रकम अभी भी सरकार को जोड़ा है और संवेय है।

उधार लेने वाले को उक्त मोटर गाड़ी भारत में लाने के समय उस पर संवेय सीमाशुल्क के संदाय मद्धे, नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियम, 1966 (जिसे इसमें प्रागे "उक्त विनियम" कहा गया है) के विनियम 246 तक के निबन्धनों पर -----रु. के प्रतिरिक्त अधिम की आवश्यकता है।

उधार लेने वाले ने सरकार को आवेदन किया है कि उसे-----रु. और अधिम दिए जाएं तथा सरकार ने उसी प्रतिभूति पर और इसमें प्राग उल्लिखित निबन्धनों पर उसे उतनी रकम उधार देना स्वीकार कर लिया है;

उधार लेने वाले ने इस प्रकार अधिम दी गई रकम से या उसके भाग से उक्त मोटरगाड़ी की बाबत सीमाशुल्क का संदाय कर दिया है;

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:—

1. उक्त करार के अनुसरण में और उधार लेने वाले को अधिम दी गई -----रु. (शब्दों में और अंकों में) को प्रतिरिक्त रकम के जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला इनके द्वारा प्रतिज्ञा कर रहा है) प्रतिफलस्वरूप, उधार लेने वाला इसके द्वारा सरकार के साथ यह करार करता है कि वह सरकार को -----रु. की रकम या उसका जोय भाग जिसका संदाय इस विलेख की तारीख तक न किया गया हो इस में दी गई रीति से किस्तों में लौटा देगा।

2. उधार लेने वाला सरकार को देय उक्त रकम -----रु. की समान संदायों द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम दिन लौटाएगा और उस समय तक देगा जब तक कि इसके द्वारा प्रतिभूत मूलधन या इन प्रतिभूति पर शोध्य उसके किसी भाग का संदाय शेष रहना है और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसे संदाय उक्त विनियम द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौती करके वसूल को जा महंगे प्रवर्ग यदि वह बारह मास से अधिक की अवधि के लिए भारत से बाहर प्रतिनियुक्त हो कर चला जाता है या भारत से बाहर किसी पर पर उसका स्थानांतरण हो जाता है और ऐसा होने पर संशम प्राधिकारों ने अधिम की शेष रकम और/या पूर्वोक्त व्याज भारत में रूप में लौटाने की इजाजत दे दी है तो उधार लेने वाला करार करता है कि वह सरकार को ऐसी बकाया रकम का संदाय जिसे नियंत्रक, रक्षा लेखा (नौसेना) के पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पंद्रह तारीख तक धन भेज कर करेगा।

3. इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देर हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से नहीं दे दी जाती है या वसूल नहीं कर ली जाती है या यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह सरकारी सेवा में नहीं रहता है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें प्रागे उधार को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी बिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरंभ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय इस विलेख और मूल विलेख के अधीन देय हो किन्तु उसका संदाय न किया गया हो, तुरन्त संवेय हो जाएगा।

4. उक्त करार और पूर्वोक्त प्रतिफल के अनुसरण में, उधार लेने वाला यह घोषणा करता है कि वह मोटरगाड़ी जिसका उल्लेख अनुसूची में (मूल विलेख की और इसकी अनुसूची में भी किया गया है) सरकार को -----रूप की उक्त राशि या इस विलेख की तारीख को शेष रकम जो उक्त मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत है तथा इसमें इसके पूर्व दी गई शर्तों के अनुसार -----रु. की उक्त राशि के लिए प्रतिभूति होगी और वे उस पर भार होंगे तथा उसका मोचन तब तक नहीं होगा या हों सकेगा जब तक कि इस विलेख और मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत धन का संदाय नहीं किया जाता है।

5. यह भी करार किया जाता है कि पूर्वोक्त मूल विलेख में उसके द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में अंतर्निष्ठ और विवक्षित सभी शक्तियाँ उपबन्ध और शर्तें मूल धन के लिए उसी रीति से पूर्णरूप से लागू की जाएंगी और प्रभावी होंगी मानो वे इससे उल्लिखित हों और उन पर विनिश्चित रूप से लागू की गई हों तथा मानो उक्त राशि मूल विलेख द्वारा प्रतिभूत अधिम का भाग हो।

## अनुसूची

मोटर गाड़ी का वर्णन

गाड़ी का नाम

सिलिंडरों की संख्या

इंजन संख्या

लागत मूल्य

इसके साथस्वरूप ..... और ..... में राष्ट्रपति के लिए और उनकी और से इस पर ऊपर लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त (उधार लेने वाले का नाम और पदनाम)  
ने

(1) .....  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति के लिए और उनकी और से

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम)  
..... (अधिकारी का नाम और पदनाम)

ने

(1) .....  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम-.....

कार्यालय-.....

टिप्पणी:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 तारीख 05 जनवरी, 1966 ..... सरकारी अधिसूचना, रक्षा मंत्रालय सं. का. नि. प्रा. 1(अ) तारीख 05 जनवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया --

(1) भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 4, के पृष्ठ 1 से 124 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. नि. प्रा. 9-अ तारीख 19 मार्च, 1974.

धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd October, 1986

SRO 19(E).—In exercise of powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966, namely :—

Short title and commencement.—1. These regulations may be called the Navy (Pay and Allowances) Amendment Regulations 1984.

2. In the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966, (1) in regulation 4, for the existing table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Categories of officers	Appendix
1	2
(a) General List Officers of all Branches (excluding Naval Aviation and Submarine Branches) upto Commander (Substantive Rank)	Appendix II
(b) General List Officers of Naval Aviation and Submarine Branches upto Commander (Substantive Rank)	Appendix III
(c) Blank	Appendix IV
(d) General List Officers (Ex-Branch List) Substantive Rank	Appendix V
(e) Special Duties List Officers (including special duties list officers of Submarine Cadre)	Appendix VI
(f) Midshipmen	Appendix VII

(2) in regulation 15,

- (i) in sub-regulation (1), the figure, brackets and letter "IV(i)" shall be deleted ;
- (ii) in sub-regulation (2), for the word, figure, brackets and letters, "Appendix IV(ii)" the words and figures, "Appendices II and III" shall be substituted ;
- (iii) in sub-regulation (4) for the words and figures "Appendices III and IV" the word and figure "Appendix III" shall be substituted ;

(3) In regulation 19, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely :—

- "(2) An increment of pay shall be given effect to from the first of the month in which it falls due whether the officer is on duty or on leave (including leave pending retirement)";

(4) after regulation 21, the following shall be inserted, namely :—

- "21A. Officers reported prisoners of War.—(1) Officers will be entitled to receive full pay and allowances appropriate to their rank (including paid acting rank), subject to adjustment in respect of the pay they receive

from the enemy while in captivity. Separation allowance if in issue prior to capture will also continue, but high altitude/uncongenial climate allowance will not be paid.

- (2) The pay and allowances, admissible as above, shall remain credited to the individual pay accounts of officers, maintained by the Naval Pay Office. From the amounts at the credit of officers, monthly allotment will be remitted, as in sub-regulation (3), at State expense by the Supply Officer-in-Charge, Naval Pay Office.

- (3) Family allotments made by officers will continue to be payable for the period for which pay is admissible. If no family allotment was in issue, fresh allotments of 45% of pay and allowances may be made to the family." ;

(5) in regulation 23, in sub regulation (2), for clause (c) the following shall be substituted, namely :—

- "(c) the officers do not avail themselves of the messing and other facilities in the ship while staying ashore except drawing free rations in kind or money in lieu thereof." ;

(6) for regulation 25, the following shall be substituted, namely :—

"25. Admissibility during leave and temporary duty.—The allowance shall continue to be admissible during periods of absence on leave and temporary duty at the same rate at which it was drawn prior to proceeding on leave/temporary duty subject to the following, namely :—

- (a) During leave (other than leave pending retirement),

- (i) four months at a time in the case of officers on annual leave, or annual leave combined with furlough, or on furlough not combined with annual leave, if any;

- (ii) four months at a time in the case of officers on sick leave, inclusive of the period of annual leave, if any, provided for in sub-clause (i) above.

Explanation I :—The limit of four months laid down in Clause (ii) above shall be extended to eight months in the case of an officer suffering from Tuberculosis/Cancer and other prolonged ailments subject to the conditions laid down in these regulations in all other respects. The grant of the allowance to an officer suffering from Tuberculosis/Cancer and other prolonged ailments during leave exceeding eight months shall be decided on merits by Government in each case.

Explanation II :—The payment of allowances during the period of leave in excess of first

four months shall also be subject to furnishing of the following certificate :—

He or his family or both continued for the period for which compensatory (city) allowance is claimed to reside at the same station (whether within its qualifying limits or in an adjoining area) from where he proceeded on leave.

(b) During temporary duty not exceeding three months.

(c) During first three months of leave if combined with temporary duty.

**Explanation :—**For the purpose of the above regulation the "family" means the officer's wife/husband, children and other persons residing with and wholly dependent upon him/her. A husband/wife/child/parents having an independent source of income is not treated as a member belonging to the family of the officer except when he is in receipt only of a gross pension (including temporary increase in pension and pension equivalent of death-cum-retirement gratuity or other retirement benefits) not exceeding Rs. 100 per month."

(7) regulation 38 to 42 shall be deleted;

(8) for regulation 44 and 45, the following shall be substituted, namely :—

"44. When the family of an officer proceeding Ex-India moves to a selected place of residence in India.—In the case of married officers whose families do not accompany them to their places of duty abroad, and in the case of single officers, the disturbance allowance will be admissible at the same rate at which they would have got transfer grant on their transfer within India.

No exchange compensation allowance will be admissible on the above rate of disturbance allowance."

"45. When officer dies abroad.—In cases of an officer, who while living with his family, dies abroad and the family returns to India at Government expense, disturbance allowance at the rates laid down in regulation 43 above will be paid to the family of the deceased officer."

(9) in regulation 48-A,

(i) for the heading "Divers retaining Fee" the heading "Diving Allowance|Retaining Fee" shall be substituted.

(ii) for the words "and Deep Divers" the words, "Deep Divers" and "Clearance Divers", shall be substituted.

(iii) for items (i) and (ii) the following shall be substituted, namely :—

"(i) Clearance Diving Officers	Rs. 150 p.m.
"(ii) Deep Diving Officers	Rs. 150 p.m.
"(iii) Ship Diving Officers	Rs. 75 p.m."

(10) in regulation 49 for Table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Rank	Nature of appointment	Rate of Allowance
1	2	3

(a) Afloat

(i) Rear Admiral Flag Officer Commanding Indian Fleet Rs. 350

(ii) Captain In Independent Command of a ship in commission Rs. 200

(iii) Commander, Lieutenant Commander, Lieutenant } In independent Command of a ship in commission Rs. 100

(b) Others

(i) Vice Admiral Flag Officer Commanding-in-Chief Rs. 300

(ii) Rear Admiral Flag Officer Commanding Western Fleet Rs. 300

(iii) Rear Admiral Flag Officer Commanding Eastern Fleet Rs. 200

(iv) Rear Admiral Flag Officer Commanding-in-Chief/Flag Officer Commanding Naval Area Rs. 200

(v) Commodore Commodore Commanding/Incharge Naval Area Rs. 100"

(11) for regulation 51, the following shall be substituted, namely :—

"51 Admissibility during absence on leave, sick list concession or temporary duty.—It will be admissible to the permanent incumbent of the appointment entitled to entertainment allowance during leave, sick list concession or temporary duty and will be stopped from the date he is struck off the qualifying appointment."

(12) in regulation 56, in sub-regulation (1), for the letters and figure "Rs. 100" the letters and figure "Rs. 250" shall be substituted;

(13) in regulation 59, for the existing table the following shall be substituted, namely :—

"TABLE

Rank	Monthly Rates	
	Full rates	Half rates
(i) Cadet/Midshipmen/Acting Sub Lieutenant/Sub Lieutenant	Rs. 35/-	Rs. 17.50
(ii) Lieutenant and above	Rs. 45/-	Rs. 22.50"

(14) In regulation 60,—

(i) In sub-regulation (1), in clause (e), after KURUSURA, the following shall be inserted, namely :—

"NISTAR, VELA, VAGIR, VAGLI and VAGHSHEER".

Explanation :—Hardlying Money at full rates to officers and sailors of NISTAR, VELA, VAGIR, VAGLI and VAGHSHEER shall be admissible from the date of their commissioning.

(ii) In sub-regulation (1), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(f) Missile Boats.—Hardlying Money shall also be payable to officers serving on board the following missile boats at the full rates, namely :—

VINASH, NIRCHAT, VIDYUT, NIRBIHK, VIJETA, NASHAK, VEER, NIPAT, PRATAP, PRALAYA, PRABAL, PRACHAND, CHAPAL, CHAMAK, CHARAG, CHATAK.

Explanation :—Hardlying Money to officers and sailors of these boats shall be admissible from the date of their Commissioning."

(iii) In sub-regulation (2), for the portion beginning with the words "Minesweepers.—and ending with the word "KATCHALL", the following shall be substituted, namely :—

"(a) Minesweepers :—

Ocean or Fleet Minesweepers.

(b) The following ships of Indian Navy :—

"GODAVARI, KUTHAR, KIRPAN, TRISHUL, TALWAR, BRAHMAPUTRA, BEAS, BETWA, KRISHNA, KAVERI, SHAKTI, MAGAR, GHARIAL, GULDAR, JAMUNA, INVESTIGATOR, KAMORTA, KADMATT, KILTAN, KAVARATTI, KATCHALL, ARNALA, ANDROTH, ANJADIP, ANDAMAN, AMINI, GAI, GHORPAD, KESARI, SHARLDUL, and SHARABH, RAJPUT, RANJIT and RANG";

(15) After regulation 60, the following sub-heading and regulation 61 shall be inserted, namely :—

"High Altitude Uncongenial Climate Allowance

61. Admissibility and Rates :—High altitude uncongenial climate allowance at the following rates shall be admissible to the officers of the Indian Navy serving in the areas defined by the Government from time to time subject to the same conditions as laid down for sailors in sub-regulation (2) of regulation 156A.

Rs. p.m.

Acting Sub Lieutenant/Sub Lieutenant	100/-
Lieutenant	125/-
Lieutenant Commander	175/-
Commander and above	200/-";

(16) in regulation 70, for the letters and figures "Rs. 1400" wherever they occur, the letters and figures "Rs. 2400" shall be substituted ;

(17) in regulation 71, for the letters and figures "Rs. 1200", the letters and figures "Rs. 2100" shall be substituted ;

(18) in regulation 76,

(i) for the heading the following shall be substituted, namely :—

"Officers on deputation to civil posts in Central/State Governments" ;

(ii) in sub-regulation (1), for the words "Officers in civil employ", the following shall be substituted, namely :—

"Officers on deputation to civil posts in Central/State Governments, except in the case of officers deputed to Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, who have to wear Service Uniform frequently, though not all the time." ;

(19) in regulation 95, in sub-regulation (2), in clause (d) for the letters and figures "Rs. 1800" the letters and figures "Rs. 2000" shall be substituted ;

(20) for sub heading "Flying Bounty" and regulation 98, the following shall be substituted, namely :—

"Flying Pay"

"98. Admissibility.—Officers of the Aviation Branch who have specialised as Pilots (P) and Observers (O) and fall within authorised Cadres of Pilots and Observers shall, in addition to their normal pay and allowances, receive a flying pay at the rates given in regulation 100. This will be treated as pay for all purposes, except for pension and gratuity. The flying pay shall be admitted on rendition of a certificate to the Supply Officer-in-Charge, Naval pay Office, Bombay as given below :—

Note 1.—Officers in receipt of flying pay in terms of regulation 54 for the period of training shall continue to be governed by those provisions.

Note 2.—Flying pay will be admissible for the period of annual leave portion of the leave pending retirement. Rendition of the certificate as required above will not be necessary for the drawal of flying pay during annual leave portion of leave pending retirement.

### FLYING PAY CERTIFICATE

(To be rendered at the end of quarters ending 31 March, 30 June, 30 September and 31 December) Certified that (Rank)....  
.....(Name).....  
(Personal No.).....  
Branch.....

- (a) \*has made adequate use of flying facilities provided to him and has maintained an acceptable level of proficiency ;

or

\*did not have any facilities or opportunity to fly, but is capable of flying on return to flying duties ;

(b) has complied with the requirements prescribed in regulation 101 ;

(c) has obtained additional life insurance coverage against all risks, including flying, through the Group Insurance (Naval) Scheme for the minimum amount of Rs. 2 lakhs.

(d) has not been declared permanently medically unfit for flying duties.

Commanding Officer/Superior Officer.

\*Delete whatever is not applicable.” ;

(21) regulation 99 shall be deleted.

(22) for regulation 100 the following shall be substituted, namely ;

“100. Rates.—(1) The rates of Flying Pay admissible to officers are as given below :—

Commander and below	Rs. 750.00 p.m.
Captain	Rs. 666.00 p.m.
Rear Admiral and above	Rs. 600.00 p.m.”

(2) Admissibility and its conditions.—Flying pay at the above rates will be admissible subject to an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees Two Lakhs being taken by the concerned officer through Group Insurance (Naval) Scheme, Survival benefits to the officer under the above Insurance Scheme as admissible will also be payable on retirement/release.

(23) (i) in regulation 101, in sub-regulation (1), for the words “Flying bounty” wherever they occur, the words “flying pay” shall be substituted ;

(ii) the following shall be added after sub-regulation (1), namely :—

“Note—The sum assured under the Group Insurance scheme and the contribution made thereunder will also reckon towards

the minimum prescribed insurance of Rs. 25000 and the average monthly premium of Rs. 150 for the purpose of grant of enhanced rates of Flying Pay.” ;

(24) regulation 102 to 104 shall be deleted.

(25) (i) in regulation 105A, for the table below sub regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

TABLE

Rank	Amount per month
Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Sub Lieutenant	Rs. 550/-”

(ii) after sub-regulation (4), the following new sub regulation shall be inserted, namely :—

“(5) Submarine pay at the above rate will be admissible subject to an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees Two Lakhs being taken by the concerned officer through Group Insurance (Naval) Scheme. Survival benefits to the officers under the above insurance scheme as admissible will be payable on retirement/release”;

(26) in regulation 111, for clause (c), the following shall be substituted, namely :—

“(c) Financial assistance at Rs. 55 per mensem only in the case of cadets whose parents or guardians have an income of less than Rs. 450 per mensem ;

Note :—In case where the parents draw income from Central/State Governments, no financial assistance shall be admissible ;” ;

(27) after regulation 111, the following sub-heading and regulations shall be inserted, namely :—

### “CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

111A.—Eligibility.—Officers who have rendered not less than one year's service and whose pay does not exceed Rs. 1200 p.m. will receive the Children Education Allowance at the rates and under the conditions prescribed in the succeeding regulations 111B and 111C.

Note—Pay for this purpose will be as defined in regulation 35.

111B. Rates.—The allowance will be admissible at the following rates :—

(a) Primary Classes :

(Class I to V) ..... Rs. 15 p.m. per child

(b) Secondary and Higher Secondary Classes :

(From Class VI upto the stage entry into three year's degree course) ..... Rs. 20 p.m. per child,



The total allowance admissible to an officer at any one time shall not exceed Rs. 60 p.m.

NOTE : Primary classes do not include kindergarten and infant classes.

111C. Conditions.—The allowance will be admissible only in those cases where an individual is compelled to send his child or children to a school away from the station at which he is posted and/or is residing, owing to any of the following :—

- (i) The absence of a school or schools of the requisite standard at that station.

Explanation I.—An Indian school shall be held to be a school not of "requisite standard" for Anglo-Indian children and vice-versa. Similarly, if a child is prevented by the tenets of his religious persuasion, from attending a school run by a body of another persuasion, such school shall be held to be a school not of the "requisite standard". Also if the teaching in a school is conducted in a language different from the language of the officer, the school shall be held to be a school not of the requisite standard.

Explanation II.—If an officer is transferred from a station where there is no school of the requisite standard, to a station where there is such a school and if he was in receipt of the allowance at the former station in respect of any child or children, he shall remain eligible for such allowance until the close of the academic year of the school in which his child or children was/were studying at time of his transfer, provided he/they continues/continue to study for that period in that school.

Explanation III.—If a child of an officer is denied admission to a school of the "requisite standard" at the station at which he is posted and or residing, because of there being no vacancy, or for any other reason and the child is, therefore, compelled to attend the school away from his place of duty and/or residence, he shall be entitled to the allowance, as if there were no schools of the requisite standard at that station.

Explanation IV.—At a station where there is no school of the requisite standard, the allowance will not be admissible if the nearest school is so situated that there is a convenient train or bus service to take the child or children near the time of opening of the school and bring them back not too long after the school is closed and the journey each way does not take more than an hour, where these conditions are not fulfilled, the allowance will be admissible irrespective of distance of the school from station at which the officer is posted and/or residing.

- (ii) Posting to a field station.

- (iii) Posting to a sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.

111D.—Where the allowance is claimed, the officer commanding of the unit/formation, will furnish the following certificate(s) to accompany the claims:—

- (a) Non-availability of a school of the requisite standard at the place of posting, or availability of school of requisite standard

at a station of posting, but denial of admission therein on the basis of information obtained from the educational authorities.

OR

- (b) Location of the unit in a field/sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.”;

(28) For regulation 129, the following shall be substituted, namely:—

“The annual increments will be allowed from the first of the month in which they fall due.”;

(29) after regulation 131, the following regulation shall be inserted, namely:—

“131A Fixation of pay on promotion :—(1) When a sailor is promoted to the next higher rank, a notional amount equal to one increment in the lower rank shall be added to the pay actually drawn by the individual on the date of his promotion and promotion and thereafter his pay fixed in higher the scale for the higher rank at the next higher stage

- (2) The notional pay in respect of sailors stagnating at the maximum of the lower scale shall be arrived at by increasing the pay by an amount equal to the last increment in the lower scale before pay is fixed in the higher scale at the stage next above the notional pay under sub-regulation (1) above.

- (3) On promotion to the rank, Master Chief Petty Officer II Class, 'Good Conduct Badge Pay' shall also be added to the basic pay drawn as Chief Petty Officer and thereafter the pay fixed as in sub-regulations above.”;

(30) after regulation 132, the following shall be inserted, namely :—

“132A. Admissibility of pay and allowances to sailors reported prisoners of war.

- (a) Sailors reported prisoners of war.—Sailors (including those holding honorary commission ranks) taken prisoners of war will be entitled to normal pay and allowances, subject to adjustment in respect of pay they receive from the enemy while in captivity. The pay and allowances of a sailor (including those holding honorary commission ranks) as prisoner of war shall be forfeited if he is dismissed/discharged from service or awarded any other punishment in consequence of his conduct resulting in his capture by the enemy or his conduct while in enemy hands as a prisoner of war. Such dismissal/dischARGE/punishment may be as a result of trial by Naval tribunal, or administratively under the provision of the Regulations for the Navy part III on the basis of Court of Enquiry proceedings or other investigations.

**Explanation.**—The term 'Pay and Allowances' referred to above will include the special compensatory allowance. If the high altitude/uncongenial climate allowance was in issue prior to capture, this will be discontinued and a special compensatory allowance at the rates given in table below will be admissible:—

TABLE

Rate of sailor	Amount per mensem Rs.
Honorary Commissioned Officer	34
MCPO I & II	29
CPOs/POs	22
LS	19
SEA/ I/SEA OO	17

(b) Family allotments.—Family allotments if already in issue prior to capture will continue. Where allotments are not being paid fresh allotments may be issued upto 60% of the sailor's net emoluments provided,

- (i) he was maintaining the allottee(s) ;
- (ii) allottees are in need of financial assistance and
- (iii) sanction of the Commanding Officer of the ship/establishment concerned has been obtained."

(31) for regulation 134-A and 134-B, the following shall be substituted, namely :—

"134A. Eligibility.—(1) All sailors (including those holding honorary ranks as commissioned officers), who have put in not less than one year's service and whose pay does not exceed Rs. 1200 p.m. will receive the Children Education Allowance at the rates and under the conditions given in the succeeding regulations.

(2) All service rendered under the Central Government in any Department or Office may be taken into account for the purpose of reckoning one year's service for the eligibility to the Children Education Allowance.

(3) Service rendered prior to their retirement or discharge from Armed Forces/Central Government service will count for computing qualifying period of one year's service for the grant of the above allowance in the case of re-employed military/Civil pensioners provided their re-employed service is continuous to their former service and the retirement or discharge was not on disciplinary grounds or at their own request.

(4) Pay for this purpose will be as defined in regulation 146;

134B. RATES.—The allowance will be admissible at the following rates :

- (a) Primary Classes.  
(Class I to V) .....Rs. 15/- p. m. per child.
- (b) Secondary & Higher Secondary Classes  
(from Class VI upto the stage entry into three year's degree course).....Rs. 20/- p. m. per child.

The total allowance admissible to a Service personnel at any one time shall not exceed Rs. 60/- p.m.

NOTE :—Primary classes do not include kindergarten and infant classes";

(32) after regulation 134-C, the following shall be inserted, namely:—

"134D. (1) From 1-11-73 Children Education Allowance will be admissible only in those cases where an individual is compelled to send his child or children to a school away from the station at which he is posted and/or is residing, owing to any of the following :—

- (a) The absence of a school or schools of the requisite standard at that station.

**Explanation No. I.**—An Indian School shall be held to be a school not of 'Requisite Standard' for Anglo-Indian Children and vice-versa. Similarly, if a child prevented by the tenets of his religious persuasion, from attending a school run by a body of another persuasion, such school shall be held to be a school not of the requisite standard. Also, if the teaching in a school is conducted in a language different from the language of the service personnel, the school shall be held to be school not of the requisite standard.

**Explanation No. II.**—If a serviceman is transferred from a station where there is no school of the requisite standard to a station where there is such a school and if he was in receipt of the allowance at the former station in respect of any child or children, he shall remain eligible for such allowance until the close of the academic year of the school in which his child or children, was/were studying at the time of his transfer, provided he/they continues/continue to study for that period in that school.

**Explanation No. III.**—If a child of a serviceman is denied admission to a school of the "requisite standard" at the station at which he is and/or is residing, because of there being no vacancy, or for any other reason and the child is, therefore, compelled to attend the school away from his place of duty and/or residence, he shall be entitled to the allowance, as if there were no school of the requisite standard at that station.

**Explanation No. IV.**—At a station where there is no school of the requisite standard, the allowance will not be admissible if the nearest school is so situated that there is convenient train or bus service to take the child or children near the time of the opening of the school and bring them back not too long after the school is closed and the journey each way does not take more than an hour. Where these conditions are not fulfilled, the allowance will be admissible irrespective of distance of a school from the

station at which the serviceman is posted and/or is residing.

- (b) Posting to a field area
- (c) Posting to a sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.
- (d) Non-availability of married accommodation for Petty Officer, Leading Seamen and Seaman I & II who are within the authorised married establishment and who are not paid compensation in lieu of quarters.
- (e) Non-availability of married accommodation in the case of Petty Officers, Leading Seamen and Seaman I & II who are not within the authorised married establishment and are not eligible for the grant of compensation in lieu of quarters.
- (f) Married accommodation allotted to Petty Officers and Leading Seamen and Seaman I & II for a period not covering one full complete academic year provided the individual is not entitled to compensation in lieu of quarters on vacation of Government accommodation.

(ii) In respect of children for whom Children Education Allowance was admissible on 31st Oct. 1973, the allowance will, however, continue to be admissible in accordance with the orders contained in Regulation 134-A et seq but at the revised rates, even if the above conditions are not satisfied, so long as he|they continues|continue to study at the same place or within the same district, where he|they was|were studying on the 31st October, 1973 and for the period for which they were|are otherwise eligible for the grant of the allowance.

(iii) Subject to the above terms and conditions service personnel who are citizens of Nepal, Sikkim and Bhutan may be granted Children's Education Allowance in respect of their Children studying in schools in their respective country|state in addition to those children studying in schools in India.

(iv) where the Children Education Allowance is claimed, the officer commanding of the unit|formation will furnish the following certificate(s) to accompany the claim :—

- (a) Non-availability of a school of the requisite standard at the place of Posting or availability of school of requisite standard at station of posting but denial of admission therein on the basis of information obtained from the educational authorities.

NOTE : In all past cases, the above mentioned certificate may be rendered by the Officer Commanding or Head of Department, without obtaining information from the concerned educational authorities due to difficulties involved in collection of such information due to lapse of time.

## OR

- (b) Location of unit in a field|sensitive area where families are specifically debarred from living with the head of the family.”;

(33) in regulation 135-A, for the figures “80 per cent” the figures “100 per cent” shall be substituted;

(34) in regulation 145, for the figures “80 per cent” the figures “100 per cent” shall be substituted;

(35) in regulation 148, in sub regulation (1), for the existing table the following shall be substituted, namely :—

TABLE

Depth		Rate for the time under water or Compression
Fathoms	Metres	
(a) Upto 20	36.58	10
(b) 20 to 30	36.58 to 54.86	15
(c) 30 to 40	54.86 to 73.15	20
(d) 40 to 50	73.15 to 91.44	30
(e) 50 to 60	91.44 to 109.73	40
(f) 60 to 75	109.73 to 137.16	55
(g) 75 to 100	137.16 to 182.88	70”;

(36) in regulation 148-A, in sub regulation (1), for the existing table the following shall be substituted, namely :—

TABLE

	Rs. per month
(i) Clearance Divers Class I	75
(ii) Clearance Divers Class II	65
(iii) Clearance Divers Class III	55”;

(37) in regulation 149, in sub-regulation (1), for item “(ii) Divers” and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“Ship’s Divers	Rs. 75/- per month
Deep Divers	Rs. 87/- per month”;

(38) in the heading to regulation 150, for the word “Examination” the word “Ex-patriation” shall be substituted;

(39) for heading “Flying Bounty” and regulation 151, the following shall be substituted, namely :—

## “Flying Pay

151. Rates.—(1) An aircrewman borne against sanctioned vacancy shall, during the period of his aircrew service, be paid in addition to his normal pay and allowances a flying pay of Rs. 374.50 per month. This will be treated as pay for all purposes except for pension and gratuity.

(2) Admissibility and its conditions.—The payment will be subject to the following conditions :—

(a) The aircrewman subscribes monthly the difference between Rs. 75 and monthly amount of the premia paid by him for sustaining endowment assurance policy/policies (Life Insurance Corporation of India or Postal Life Insurance Fund) covering aviation risks also, to the Armed Forces Personnel Provident Fund in addition to the compulsory minimum rate of subscription payable to the Armed Forces Personnel Provident Fund. Such additional subscription will commence from the pay of the month following that in which he qualifies for the flying pay.

(b) The aircrew man obtains an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees One Lakh through the Group Insurance (Naval) Scheme. Survival benefits to the personnel under the above insurance scheme as admissible will also be payable on retirement/release.

(3) The flying pay shall be admitted on rendition of a certificate as given below :—

#### "FLYING PAY CERTIFICATE"

(To be rendered at the end of quarters 31 March, 30 June, 30 September and 31 December)

Certified that (Service No.) \_\_\_\_\_  
Rank \_\_\_\_\_ (Name) \_\_\_\_\_  
Trade \_\_\_\_\_

(a) \*has made adequate use of flying facilities provided to him and has maintained an acceptable level of proficiency.

\*did not have any facilities or opportunity to fly, but is capable of flying on return to flying duties.

(b) has fulfilled the conditions regarding minimum additional contribution to Armed Forces Personnel Provident Fund/Compulsory Insurance Cover.

(c) has not been declared permanently medically unfit for flying duties.

Commanding Officer/  
Superior Officer.

\*Delete whatever is not applicable.”;

(4) Flying pay will be admissible for the period of annual leave portion of leave pending retirement. Rendition of the certificate as required above will not be necessary for the drawal of flying pay during annual leave portion of leave pending retirement.

(40) In regulation 152, in sub-regulation (2) for letter and figures, “Rs. 100” the letter and figures “Rs. 250” shall be substituted;

(41) in regulation 154, in sub regulation (2), for the letters and figures “Rs. 2.00” the letters and figures “Rs. 7.00” shall be substituted;

(42) in regulation 155,

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely :—

“(1) Hardly money shall be payable to sailors including those belonging to record parties under the conditions specified in Regulation 58 at full or half rate according to the classification of ships laid down in Regulation 60.”;

(ii) in sub-regulation (2), for the table the following shall be substituted, namely :—

“TABLE

Sailors	Monthly Rates	
	Full Rates	Half Rates
	Ruppes	Ruppes
Master Chief Petty Officer I & II	35.00	17.50
Chief Petty Officers	35.00	17.50
Petty Officers	30.00	15.00
Leading Seamen	30.00	15.00
Seamen I and II	25.00	12.50
Boys	20.00	10.00”

(43) after regulation 156, the following heading and regulation shall be inserted, namely :—

#### “High Altitude/Uncongenial Climate Allowance

156-A. Admissibility and rates.—High altitude/uncongenial climate allowance at the following rates shall be admissible to sailors serving in the area defined by the government from time to time, under the following conditions :—

	Ruppes per month
Master Chief Petty Officer I & II }	90
Chief Petty Officer }	
Petty Officer }	70
Leading Seaman }	
Seaman I & II }	50

(2) This allowance shall be admissible from the date on which an individual arrives in the specified area on being posted to a unit/formation in that area and subject to the following exceptions; it shall cease on the date following that on which he leaves the area.

Exceptions.—An individual who is absent from the area for a maximum period of 14 days in one or more of the following circumstances shall continue to receive the allowance provided he returns to the area in which the allowance is admissible.

(i) when placed on the sick list;

(ii) when on causal leave;

(iii) when on temporary duty;

Explanation I.—The allowance shall not be admissible to individuals holding posts elsewhere who proceed on temporary duty to the specified area. However, the allowance shall be admissible to individuals holding posts elsewhere who are attached to units etc. in the specified area for a continuous period of more than 14 days, if they are not in receipt of daily allowance as admissible to individuals proceeding on temporary duty.

**Explanation II.**—Individuals serving with detachments within the specified area shall be treated as posted for the purpose of admissibility of the allowance, if the detachments are deployed in the area for a continuous period of more than 14 days. Conversely, individuals of units/formations which are located within the defined area, who move with detachments outside the area shall cease to be eligible for the allowance if the detachments remain outside the area for a continuous period of more than 14 days.

**Explanation III.**—The allowance shall not be admissible to individuals when they are absent from the area on annual leave, sick leave or any other leave except casual leave.

**Explanation IV.**—The allowance shall be admissible while on transit from one qualifying area to another.

(3) The special compensatory allowance admissible for concessional area shall not be admissible in addition to this allowance”;

(44) in regulation 162, after clause (1) the following shall be inserted, namely :—

“(m) When attending NCC camps at outstations where rations cannot be supplied by the Government

(i) upto 30 days Commander NCC Group HQ

(ii) Beyond 30 days Director, NCC States.”;

(45) after regulation 172-B, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely :—

“Sea Duty Allowance

172-C. Admissibility and rates.—This allowance at the following rates will be admissible to all sailors serving afloat, including those attached on temporary duty, during the periods their ships are actually away from the base ports.

Rank	Rupees per month
Master Chief Petty Officers I & II } Chief Petty Officers	53
Petty Officers	38
Leading Seaman	33
Seamen I and II	30”;

(46) in regulation 174, for the table, the following shall be substituted, namely :—

“TABLE

Category	Rupees per annum”
1st Class } Survey Recorder	Master Chief Petty Officers Class I & II 700
	Chief Petty Officer 600
	Petty Officers and below 500
	2nd class Survey Recorder 400
	3rd class Survey Recorder 300”;

(47) in regulation 176, in sub-regulation (1), in the table, before entries relating to the Chief Petty Officer, the following entries shall be inserted, namely :—

“Rating	Daily Rate	Monthly ceiling
Master Chief Petty Officer Class I & II	Rs. 2/-	not laid down”;

(48) (i) in regulation 176-A, in sub-regulation (1), for the table, the following shall be substituted, namely :—

“Rank	Rupees per month
Master Chief Petty Officer I and II	350
Chief Petty Officer	300
Petty Officer	275
Leading Seaman	265
Seaman I and II	250”;

(ii) after sub-regulation (4), the following new sub-regulation shall be inserted, namely :—

“(5) Submarine pay at the above rates will be admissible subject to an additional life insurance cover against all risks for a minimum amount of Rupees One Lakh being taken by the concerned personnel through the Group Insurance (Naval) Scheme. Survival benefits to the personnel under the above insurance scheme as admissible will also be payable on retirement|release.”;

(49) after regulation 176-A, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely :—

“176-B. Shorthand allowance. —Shorthand allowance @ Rs. 30/-p.m. will be admissible to (a) one Leading Writer|writer when performing the duties of the Stenographer in Ships commanded by Captains and in Leaders of Squadrons; (b) one Chief Petty Officer Writer|Petty Officer Writer on the staff of the Flag Officer Commanding, Indian Fleet when performing the duties of the stenographer on the following conditions :—

(i) The allowance will be paid only if the individual is adjudged as qualified stenographer and passes the prescribed trade tests.

(ii) The allowance will only be admissible while serving on board a ship when civilian stenographers are not available.”;

(50) after regulation 177-A, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely :—

#### SUBSISTENCE ALLOWANCE TO FAMILIES OF SAILORS AWARDED IMPRISONMENT|DETENTION

177-B. Admissibility and Rates.—A subsistence allowance of Rs. 60/- per month shall be paid to the family of married sailors who are awarded imprisonment or detention by their Commanding Officer of by a Court Martial and who are not dismissed from

service. The allowance shall be payable during the period the pay and allowances are forfeited. The allowance shall be adjusted against any credits that might later become available by way of remission or acquitted to the individuals.

Note :When the above amount is remitted by money order, the money order commission shall be charged to the Government.”;

(51) after regulation 178-A, the following sub-heading and regulation shall be inserted, namely :—

“Bonus

178-B — Admissibility of Bonus.—Bonus will be credited in the individual running ledger account of sailors at the rate of Rs. 43.75 per quarter on each completed sum of Rs. 50/- of credit balance in the ledger account as it stood at the end of each quarter less net pay and allowances for the last month of the quarters. Sums of less than Rs. 50/- in the balance will be disregarded.

In the case of individuals, who become casualties, bonus will be credited upto the last day of the quarter preceding that in which their accounts are finally closed.

No income tax will be charged on this bonus.”;

(152) for regulation 191, the following shall be substituted, namely :—

“191. Gallantry decorations awarded after the 15th August,

1947 — Rates and conditions.—(1) The rates of special pension per month attached to gallantry decorations awarded to any officer or sailor shall be as given hereunder :—

Gallantry Award	Pension per month
(a) (i) Param Vir Chakra	Rs. 100.00
(ii) Each Bar to Param Vir Chakra	Rs. 40.00
(b) (i) Maha Vir Chakra	Rs. 75.00
(ii) Each Bar to Maha Vir Chakra	Rs. 25.00
(c) (i) Vir Chakra	Rs. 50.00
(ii) Each Bar to Vir Chakra	Rs. 20.00
(d) (i) Ashoka Chakra	Rs. 90.00
(ii) Each Bar to Ashoka Chakra	Rs. 35.00
(e) (i) Kirti Chakra	Rs. 65.00
(ii) Each Bar to Kirti Chakra	Rs. 20.00
(f) (i) Shourya Chakra	Rs. 40.00
(ii) Each Bar to Shourya Chakra	Rs. 16.00

The above rates will take effect from 1st January 1972 and will be applicable to all awards made after 15th August 1947.

(2) The pensions shall be admissible with effect from the date of the act or event in respect of which the decoration is granted.

(3) Pension for only one decoration (and a bar or bars thereto) shall be drawn at a time; and the less favourable rate of pension shall be relinquished from the date of grant of the higher decorations.

(4) The pension shall be admissible to the recipient of the decoration till his death, and on his death to his widow who has been lawfully married to him by valid ceremony; and she shall continue to receive the pension until her re-marriage or death :

Provided that such payment shall be continued to a widow who remarries her late husband's brother and continues to live with the deceased's other living heirs who are eligible for family pension.

Explanation.—Ordinarily, the pension payable to an officer/sailor shall, on his death, be paid only to the widow who was his first wife. But with the special sanction of the Central Government, such pension may be divided equally between all the widows of the recipient, and payments to all the widows shall cease when the pension to the widow who was his first wife, ceases to be payable as hereinbefore provided.

(5) When the award is made posthumously to a bachelor, the monetary allowance shall be paid to his father or mother, and in case the posthumous awardee is a widower, the allowance shall be paid to his son below 18 years or unmarried daughter as the case may be.

(6) Pension under this regulation is liable to be forfeited on conviction for the following offences and shall be stopped with effect from the date indicated in the Gazette of India notifying the forfeiture of the award namely :—

- (a) Treason
- (b) Sedition
- (c) Mutiny
- (d) Cowardice
- (e) Desertion during hostilities
- (f) Murder
- (g) Dacoity
- (h) Rape
- (j) Unnatural offences.

Such pension as may have been forfeited shall become payable on the restoration of the award as notified in the Gazette of India.”;

(53) for regulations 209 and 210, the following shall be substituted, namely :—

“209. Compensation in respect of officers.—(1) If any article of equipment, clothing (including personal clothing), books, instruments, tools or accessories being the personal property of an officer is lost, damaged or destroyed under circumstances mentioned below the Government shall be liable to pay compensation to the officer provided the loss, damage or destruction was not due to the negligence on part of the claimant.

- (i) When the loss, damage or destruction is caused by the action of the enemy or insurgents;
- (ii) When the loss, damage or destruction is due to an accident occurring when the officer was travelling by road, river, rail, sea or air on duty;

- (iii) When the articles are lost, damaged or destroyed in a Naval Ship or a Government building, whether owned, hired or rented, or in a tent in use under appropriate authority and for a recognised service purpose, provided the officer had no option but to live in such accommodation for the performance of his Naval duties.
- (iv) When the articles are lost, damaged or destroyed, while in transit by rail, road, air, river or sea provided that they were in the charge and custody of Government at that time.
- (v) When the articles are destroyed under the orders of the competent authority;
- (vi) When the articles are lost, damaged or destroyed during the performance of duty.

2. Compensation will be sanctioned on the basis of the recommendations of a Board of Inquiry convened by the Administrative Authority. In respect of items which an officer is required to purchase out of outfit allowance, the Board of Inquiry will determine the proportion which the cost of such item destroyed bears to the total cost of all items purchased out of initial outfit allowance granted at the time of commissioning and the compensation will be limited to the same proportion of the initial outfit allowance.

3. Articles of equipment clothing or necessities which are issued free will be replaced by Government on the recommendations of the Board of Inquiry.

4. Compensation for the loss of clothing (including personal clothing) equipment and articles occurring in the above-mentioned circumstances may also be sanctioned by the Administrative authority if recommended by the Board of Inquiry, subject to a limit of Rs. 1,000/- in each individual case. Compensation will not cover items like jewellery, refrigerators, air conditioners and other expensive articles. The competent authority will take into account the cost price of the articles, the period for which they had been used, and their depreciation while assessing the amount of compensation. Where the Board of Inquiry recommends compensation in excess of the above amount the case may be referred to Government for consideration on merits.

21. Compensation in the case of sailors.—(1) If any article of equipment, clothing (including personal clothing), books, instruments, tools or accessories, being the personal property of a sailor is lost, damaged or destroyed under circumstances mentioned below, the Government shall be liable to pay compensation to the sailor provided the loss, damage or destruction was not due to the negligence on part of the claimant.

- (i) When the loss, damage or destruction is caused by the action of the enemy or insurgents;
- (ii) When the loss, damage or destruction is due to an accident occurring when the individual was travelling by road, river, rail, sea or air on duty;

- (iii) When the articles are lost, damaged or destroyed in a Naval Ship or a Government building whether owned, hired or rented, or in a tent in use under proper authority and for a recognised service purpose provided the individual had no option but to live in such accommodation for the performance of his duties;
- (iv) When the articles are lost, damaged or destroyed while in transit by rail, road, air, river or sea provided they were in the charge and custody of Government at that time;
- (v) When the articles are destroyed under the orders of the competent authority;
- (vi) When the articles are lost, damaged, or destroyed during the performance of duty.

(2) Compensation will be sanctioned on the basis of the recommendation of a Board of Inquiry by the Administrative authority. The maximum limit for compensation in respect of personal clothing will be the "frozen rates."

(3) Articles of equipment, clothing or necessities which are issued free, will be replaced by Government on the recommendation of the Board of Inquiry.

(4) Compensation for the loss of clothing (including personal clothing) equipment and articles occurring in the above mentioned circumstances may also be sanctioned by the Administrative Authority of record by the Board of Inquiry, subject to a limit of Rs. 500/- in each individual case. Compensation will not cover items like jewellery, refrigerators, air conditioners and other expensive articles. The competent authority will take into account the prices of the articles, the period for which they had been used, and their depreciation while assessing the amount of compensation. Compensation in the case of civilian clothing will be restricted to the civilian clothing allowance. Where the Board of Inquiry recommends compensation in excess of the above amount the case may be referred to Government for consideration on merits".

(54) regulation 220 of the said Regulations is amended as under :—

Insert the words "other than those falling under Regulations 209 and 210" after the words "compensation" occurring in line 2 of the above Regulation.

(55) for Regulation 246, the following shall be substituted, namely :—

"246. Advance for the payment of customs duty.—Officers holding regular posts abroad and those sent on deputation to foreign Governments whose term of assignment is one year or more, who are entitled to motor car advances, under Regulation 245, may be sanctioned advances by the Central Government to enable them to meet the customs duty on the cars purchased abroad and being brought by them to India on transfer. The authority competent to sanction these advances shall be the Government of India.

**NOTE :—**No interest shall be chargeable on the advance sanctioned for the payment of customs duty.

(2) The advance for the payment of customs duty in India, shall be treated as a separate advance and shall not be merged with the advance, if any, already sanctioned for the purchase of motor car.

(3) The amount of advance for the payment of customs duty shall be Rs. 12000 or the customs duty actually payable. Where an officer has already drawn an advance for the purchase of motor car, which is not fully repaid, the amount of customs duty advance together with the outstanding balance of motor cars advance shall not exceed Rs. 14000 or 14 months' pay (17 months' pay in the case of officers drawing pay less than Rs. 1000/- p.m.) whichever is less.

**NOTE:—**The amount of advance granted for the payment of customs duty shall in no case exceed the customs duty actually payable.

(4) The amount of customs duty advance shall be adjusted against the amount subsequently reimbursed to the officer concerned for the payment of customs duty. In case the principal amount of the advance cannot be adjusted in full against the amount reimbursed in terms of the orders in force, the outstanding amount shall be recovered in lump sum from the pay of the officer concerned in the month immediately following that in which the customs duty is reimbursed.

(5) The recovery in the case of an officer who is due to retire shall be so regulated that the outstanding advance is recovered in full by the time the last pay is issued to the officer before retirement.

(6) The advance for the payment of customs duty shall not be admissible to officers sent abroad, but not entitled to motor car advance under regulation 245 e.g., those sent on deputation abroad on temporary duty.

(7) The other conditions prescribed for the sanction of an advance for the purchase of a motor car shall apply mutatis-mutandis in the case of the advance for the payment of customs duty.

(8) The forms of mortgage bond to be executed for the undermentioned advances are laid down in Appendices XI-C and XI-D:—

(a) When only one advance is sanctioned for the purchase of a motor car or for the payment

of customs duty or when only one advance is sanctioned for both purposes—Appendix XI-C and;

(b) Where the advance for the payment of customs duty is sanctioned after the motor car has been purchased with an earlier advance—Appendix XI-D.”

(56) after regulation 246, the following regulation shall be inserted, namely :—

“246 A. Additional conditions—In cases where the officers are entitled to draw advance under regulation 246 but are not entitled to the reimbursement of customs duty on the cars purchased abroad and brought by them to India, for which import licence is ordinarily admissible the advance shall be subject to the following conditions :—

(a) The amount of advance for the payment of customs duty should be restricted to Rs. 12000/- or the customs duty actually payable whichever is less. Further, the amount of customs duty advance, together with the outstanding balance in respect of the advance, if any, drawn previously for the purchase of the car but not fully repaid, should not exceed Rs. 14000/- or 14 months pay (17 months pay in the case of officers drawing pay less than Rs. 1000/- p.m.) whichever is less.

(b) The sanction to this advance shall not be imbursement of customs duty which shall be cited as argument for claiming reimporting re-governed strictly by the Government orders issued on the subject.

(c) The officer will not be allowed to sell his car till the advance is repaid.

(d) The Head of the Missions and the Defence Ministry should certify that the maintenance of car was necessary by the Government servant in the public interest in the country or countries of posting abroad and would also be necessary in the efficient discharge of his duties in India.

(e) The car shall be kept comprehensively insured including insurance against riot and civil commotion by the individuals as long as any amount of the advance alongwith interest thereon remains outstanding.



- (f) The advance for the payment of customs duty in India should be treated as a separate advance and should not be merged with the advance, if any, already sanctioned for the purchase of the motor car.
- (g) The advance granted for the payment of customs duty will be recoverable in not more than sixty instalments. The recovery of customs duty advance should not be related to the outstanding recoveries in respect of the earlier advance, if any, sanctioned for the purchase of the motor car, the recoveries against the earlier advance, will be made in accordance with the terms and sanction thereof even after the sanction of this advance.
- (h) The recovery of the customs duty advance in the case of an officer who is due to retire should be so regulated by stepping up the amount of instalments that the advance together with the interest thereon is recovered in fully by the time the last pay is drawn by the officer before retirement.
- (i) In the case of quasi-permanent or temporary officer, the surety of a permanent Central Government servant of comparable or higher status should be obtained before sanctioning the advance.
- (j) The authority competent to sanction the advance will be the Government of India. The other conditions prescribed for the sanction of an advance for the purchase of a motor car will apply mutatis mutandis in the case of this advance.
- (k) These orders will not apply to the officers not holding regular posts abroad i.e. those sent on deputation abroad on Temporary duty. Officers sent on deputation to United Nations Organisations and its various agencies shall, however, be entitled to the grant of advance.
- (l) The advance will bear interest at the same rate as is applicable to the advance for the purpose of motor car."

(57) For regulation 248, the following regulation shall be substituted, namely :—

"248. Sanctioning authorities (1) Officer to whom advances for the purchase of motor cycles are admissible and the authorities

empowered to sanction them are given in the table below :—

To whom admissible	Sanctioning Authority
1	2
(a) All Naval Officers (other than the Chief of the Naval Staff) serving at Naval Headquarters	The Chief of the Naval Staff
(b) All Naval Officers serving in Naval Shore Establishment outside Naval Headquarters	(i) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay. (ii) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, VISHAKHAPATNAM. (iii) The Flag Officer, Commanding, Southern Naval Area, Cochin. As the case may be.
(c) Naval Officer Serving in afloat appointments	(i) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay. (ii) The Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, VISHAKHAPATNAM. (iii) The Flag Officer, Commanding, Southern Naval Area, Cochin as the case may be.
(d) Instructional Staff and student officers, Defence Services Staff College, Wellington.	Commandant, Defence Services Staff College, Wellington.
(e) Staff and Student Officers, paid from Defence Services Estimates, National Defence College, New Delhi.	Commandant, National Defence College, New Delhi.

(2) The advance shall be upto Rs. 3500 or ten months pay or anticipated price of the motor cycle, whichever is least",

(58) in regulation 253, for the existing clause (a) to (f), the following shall be substituted, namely :—

"(a) Naval Officer-in-Charge	In the case of personnel serving under them.
(b) Commanding Officer of Shore Establishment	In the case of personnel serving under them.
(c) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Bombay	In all other cases as the case may be.
(d) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, Vishakhapatnam	
(e) The Flag Officer Commanding, Western Fleet	In all other cases as the case may be.
(f) The Flag Officer Commanding, Eastern Fleet	
(g) The Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command, Cochin	

(59) For regulation 257B, the following shall be substituted, namely :—

257B—Advance of pay on even of important festivals :—

(1) Eligibility sailors serving on regular engagement, Boys and Apprentices, whose pay does not exceed Rs. 600/- per month may be granted advance of pay on the eve of important festivals subject to the following terms and conditions :—

- The amount of advance will be Rs. 200/- or one month's pay (including appointment pay, Good Conduct pay and acting allowance) whichever is less.
- The advance must be drawn before the festival concerned. It is admissible only to those on duty and whose Individual Running Ledger Accounts do not show debtor balances at the time the advance is drawn.
- The advance will be recovered in not more than ten equal monthly instalments, the first recovery commencing with the next month's regular payment. The amount of each instalment will be rounded off to the nearest rupee, the balance being recovered in the last instalment.
- The advance will be admissible only on one occasion in a calendar year. The Commanding Officers of ships and establishments will

fix the festival occasions on which advance will be allowed, after taking into consideration the importance attached locally to such festival.

(c) A second festival advance should not be sanctioned till the earlier festival advance sanctioned on a previous occasion has been recovered in full.

(f) In case of festival falls twice in a calendar year, the advance will be admissible only on one occasion.

(2) Sanctioning Authority.—The Commanding officer of the ship/establishment is authorised to grant advance of pay on such occasion. He may at his discretion sanction such advance to sailors not serving on a regular engagement who have completed three years of continuous service and are likely to continue in service till the adjustment of the advance.

Explanation—The Republic Day and Independence Day may be treated as festival occasions for the purpose of advance of pay.

(60) In regulation 266, for the existing table, the following shall be substituted, namely :—

"Honorary Sub Lieutenant	Rs. 1000/- per month
Honorary Lieutenant	Rs. 1100/- per month"

(61) In regulation 269, for the figures "720", the figures "1440" shall be substituted;

(62) After regulation 272, the following shall be substituted, namely :—

#### "Sea Duty Allowance

273. Admissibility and Rates—Sea Duty Allowance at the rate of Rs. 53/- per month will be admissible to all Honorary Commissioned Officers serving afloat, including those attached on temporary duty, during the periods their ships are actually away from the base ports."

#### High Altitude/Uncongenial Climate Allowance

274. Admissibility and Rates.—Honorary Commissioned Officers shall be entitled to High Altitude/Uncongenial Climate Allowance at the rate of Rs. 90/- per month under the conditions applicable to sailors as laid down in regulation 156A."

(63) For Appendices II and III, the following shall be substituted, namely :—

## "Appendix-II

Rates of pay for General List Officers of all branches

(excluding Naval Aviation and Submarine branches)

(See regulation 4)

Year of Service	Acting Sub-Lieutenant Rs. p.m.	Sub-Lieutenant Rs. p.m.	Lieutenant Rs. p.m.	Lieutenant Commander Rs. p.m.	Acting Commander Rs. p.m.	Commander Rs. p.m.
1	750	—	—	—	—	—
2		830	—	—	—	—
3		870	—	—	—	—
4			1100	—	—	—
5			1150	—	—	—
6			1200	—	—	—
7			1250	—	—	—
8			1300	—	—	—
9			1350	—	—	—
10			1400	1450	—	—
11			1450	1500	—	—
12				1550	1750	—
13				1600	1750	—
14				1650	1750	—
15				1700	1750	—
16				1700	1750	—
17				1750	1800	1800
18				1800	1850	1850
19				1800	1900	1900
20				1800	1950	1950
21				1800	1950	1950
22				1800	1950	1950
23				1800	1950	1950
24				1800	1950	1950

Time Scale Commander	Rs. 1900/- p.m.
Captain	Rs. 1950-75-2100-100-2400 Acting or Substantive
Rear Admiral	Rs. 2500/-125/2750
Vice Admiral	Rs. 3000/- p.m.
Chief of Naval Staff	Rs. 4000/- p.m.

Note 1.—Commodores will receive rates of pay to which entitled according to their seniority as Captains.

manders (Selective) for a period not exceeding six months at a time shall draw the pay admissible to the latter.

Note 2.—Officers substantively promoted to the rank of Commander by time scale who are not held against authorised appointments will draw a fixed pay of Rs. 1900/- per month. However, such officers when appointed to officiate in the vacancies tenable by Com-

Note 3.—Officers of other than aviation and submarine Branches granted higher paid acting rank of Lieutenant Commander will receive pay as under :—

Till the completion of	
8th year of service	Rs. 1350/-
9th year of service	Rs. 1400/-

## APPENDIX—III

Rates of pay for General List Officers of Naval Aviation and Submarine Branches

(See Regulation 4)

Year of Service	Acting Sub-Lieutenant	Sub-Lieutenant	Lieutenant	Lieutenant Commander	Acting Commander	Commander
	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.	Rs. p.m.
1	825					
2		910				
3		950				
4			1200			
5			1250			
6			1300			
7			1350			
8			1400	1450		
9			1450	1500		
10			1500	1550		
11			1550	1600	1750	
12				1650	1800	1800
13				1700	1850	1950
14				1700	1900	1900
15				1750	1950	1950
16				1800	1950	1950
17				1800	1950	1950
18				1800	1950	1950
19				1800		
20				1800		
21				1800		
22				1800		
23				1800		
24				1800		

Time Scale Commander  
Captain  
Rear Admiral

Rs. 1900/- p.m.  
Rs. 1950-75-2100-100-2400 }  
Rs. 2500-125/2-2750 }

Acting or Substantive

Vice Admiral

Rs. 3000/- p.m.

Chief of the Naval Staff

Rs. 4000/- p.m.

Note 1 — Commodores will receive rates of pay to which entitled according to their seniority as Captains.

Note 2 — Officers substantively promoted to the rank of Commander by Time-Scale who are not held against authorised appointments will draw a fixed pay of Rs. 1800/- per month. However, such officers when appointed to officiate in the vacancies tenable by Commanders (Selective) for a period not exceeding six months at a time shall draw the pay admissible to the latter.

Note 3 — Officers of Aviation and Submarine Branches granted higher paid acting rank of Lt. Commanders will receive pay as under:—

Till the completion of

7th year of service—Rs. 1400 per month.”;

(64) Appendix IV shall be deleted;

(65) Substitution of Appendices V, VI & VII for appendices V, VI and VII, the following shall be substituted, namely :—

#### “APPENDIX V

Rates of pay for General List officers (Ex-Branch List)  
Substantive Rank

(See regulation 4)

Lieutenant Commander	Rs. per month
On promotion	1550
After 1 year's service	1600
After 2 year's service	1650
After 3 year's service	1700
After 4 year's service	1700
After 5 year's service	1750
After 6 year's service	1800
After 7 year's service	1800
After 8 year's service	1800
After 9 year's service	1800
After 10 year's service	1800
After 11 year's service	1800
After 12 year's service	1800
Commander	
On promotion	1850(*)
After 1 year's service as such	1900
After 2 year's service as such	1950
After 3 year's service as such	1950
After 4 year's service as such	1950

Note: An Ag Cdr will be entitled to fixed pay of Rs. 1800.

Captain	Same as for Captain General List
---------	-------------------------------------

#### APPENDIX VI

Rates of pay for Special Duty List Officers (including Special Duties List Officers of Submarine Cadre).

(See regulation 4)

Special Duties List	Rs. per month
Action Sub-Lieutenant (SD) (On probation)	750
Acting Sub-Lieutenant (Temporary/ Sub-Lieutenant (SD)	830-40-950
Lieutenant (SD)	1100-50-1500
Lieutenant Commander (SD)	1550-50-1700-1700- 50-1800
Commander (SD)	1800-50-1950
Special Duties List-Submarine Cadre	
Acting Sub-Lieutenant (SD) (On probation)	825
Acting Sub-Lieutenant (SD) (Temporary/Sub-Lieutenant (SD)	910-40-1030
Lieutenant (SD)	1200-50-1550
Lieutenant Commander (SD)	1650-50-1700-1700- 50-1800
Commander (SD)	1800-50-1950

#### APPENDIX VII

##### Midshipmen Basic Pay

(See regulation—4)

Midshipmen Basic Pay.....Rs. 56 per mensem.\*;

(66) Substitution of Appendix IX.—for Appendix IX the following shall be substituted, namely :—

#### APPENDIX IX

##### Rate of Pay for Sailors

(See regulation 125)

##### GROUP 'A'

Branches : All Artificers and Mechanics

Apprentices/ Artificers	Mechanicians	Rs. per month
Apprentice 1st year	—	195
Apprentice 2nd year	—	200
Apprentice 3rd year	—	205
Apprentice 4th year	—	210
Artificer V Class	—	240-6-246
Acting Artificer IV Class	—	300-8-308
Artificer IV Class	Mechanician IV Class	340-8-356
Artificer III Class	Mechanician III Class	391-10-41
Artificer II Class	Mechanician II Class	435-10-485
Artificer I Class	Mechanician I Class	500-10-550
Chief Artificer	Chief Mechanician	565-15-640
Master Chief Petty Officer II		620-20-740
Master Chief Petty Officer I		725-25-825

##### GROUP 'B' (Non Artificer)

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	215
Seaman II	230-6-242
Seaman I	240-6-312
Loading Seaman	250-6-310-8-326
Petty Officer	300-8-380
Chief Petty Officer	385-15-475
Master Chief Petty Officer II	480-20-600
Master Chief Petty Officer I	600-25-700

Note: On acquiring any of the Specialist qualifications given below, Medical Assistants, will for the purpose of pay be upgraded from Group 'B' to rates of pay admissible to corresponding categories of Naval Aviation Sailors.

## NON ARTIFICER SAILORS OF SUBMARINE ARM

Name of the specialist qualification courses	Class
(1) Advance Nursing	I & II
(2) Medical Stores	I & II
(3) Laboratory Assistant & Laboratory Technician	I & II
(4) Operating Room Technician	I & II
(5) Radiography (X Ray Assistants and/or Technicians)	I & II
(6) Special Diseases	I & II
(7) Physiotherapy	I & II
(8) Hygiene	I & II
(9) Psychiatric Nursing	I & II
(10) Dental Operating Room Assistant	I & II
(11) Blood Transfusion Assistant	I & II
(12) Dispenser	I & II
(13) Dental Technician/and/or Dental Hygienist	I & II

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	245
Seaman II	255-6-267
Seaman I	285-7-369
Leading Seaman	310-7-380-8-396
Petty Officer	360-8-440
Chief Petty Officer	455-15-545
Master Chief Petty Officer II	550-20-670
Master Chief Petty Officer I	650-25-750

Note: Artificer/Mechanician sailors of Submarine Arm will get the Group 'A' rates of pay

## GROUP 'C' (Non-Artificer)

Rank	Rs. per month
Seaman Under Training	200
Seaman II	210-5-225
Seaman I	220-5-280
Leading Seaman	235-6-295-8-311
Petty Officer	300-8-380
Chief Petty Officer	385-15-475
Master Chief Petty Officer II	480-20-600
Master Chief Petty Officer I	600-25-730

## BOYS

	Rs. per month
On enrolment	55.00
On completion of initial training	58.00
Boy Seagoing	80.00

General Note: In addition to the scales of pay indicated above 'Good Conduct Badge Pay' will be admissible at the existing rates and under the existing conditions."

(67) in Appendix XI-C,—

(i) below the heading, for the brackets, words and figures "(see regulation 239 (4) and 243)" the brackets, words and figures "(see regulation 239(4), 243 and 246)" shall be substituted ;

(ii) The following note shall be added at the end namely :—

"Note :—Since no interest is chargeable on the advance sanctioned for the payment of custom duty the term interest used in the agreement form, shall not be applicable to this advance."

(68) For 'Appendix XI-D' the following Appendix shall be substituted, namely :—

## "APPENDIX XI—D

Form of Mortgage Bond for an Advance for the payment of Customs Duty on a Motor Vehicle Purchased with a separate earlier Advance

Note: Petty Officer Air Fitters/Petty Officer Air Ordnance Fitters selected to undergo Aircraft Mechanician Course, on being advanced to Aircraft Mechanician 4th Class, shall continue to receive pay in their existing scale until such time as they reach the same level of pay as Aircraft Mechanicians.

(See regulation 146)

THIS DEED OF FURTHER CHARGE is made this ..... day of..... BETWEEN..... son of..... hereinafter called "the Borrower", which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his successors and assignee) of the one part and the President of India, (hereinafter called "the Government", which expression shall, unless excluded by or repugnant to the subject or context, include his successors and assignees) of the other part.

Whereas by Deed of Mortgage dated the..... day of..... the Borrower by mortgaged to the Government the motor vehicle described in the Schedule thereto to secure the motor vehicle purchase advance of Rs. .... at the rate and on conditions mentioned in the said Deed of Mortgage (hereinafter referred to as the Principal Deed).

And whereas out of the said sum of Rs. .... advanced to the Borrower by Government a sum of Rs. .... towards principal as per the term of Principal Deed still remain due and payable to the Government.

And whereas the Borrower being in need of a further advance of Rs. .... on the terms of regulation 246 of the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 1966 (hereinafter referred to as "the said regulations") towards payment of customs duties payable on the said vehicle at the time of bringing the same into India.

And whereas the Borrower has approached the Government for an advance of further sum of Rs. .... and the Government has agreed to lend the same on the same security and on terms hereinafter expressed.

And whereas the Borrower has paid the customs duty in respect of the said motor vehicle with or partly with the amount so advanced.

Now this deed witnesseth :—

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the further sum of Rs. .... (in words as well as in figures) advanced to the Borrower (receipt of which the Borrower hereby acknowledges) the Borrower hereby covenants with the Government to repay to the Government the sum of Rs. .... or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by instalments in the manner hereinafter.

2. The Borrower shall repay the said sum due to the Government by equal payments of Rs. .... each on the first day of every month so long as the principal moneys hereby secured or any part thereof due on this security remain unpaid and the Borrower doth agree that such payments may be recovered by monthly deductions from his salary to the manner provided by the said regulations "or where, in the event of his proceeding on deputation out of India for a period exceeding 12 months or of his being transferred to a post outside India, the competent authority has allowed repayment of the amount of advance remaining unpaid and/or interest as aforesaid on the happening of such an event in rupees in India, the Borrower doth hereby agree to pay to Government such dues by remittance through Bank Draft drawn by the 15th of every month in favour of the Controller of Defence Accounts (Navy)"

3. It is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of the principal shall not be paid or recovered in the manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower dies or at any time ceases to be in Government service or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in or of the said motor vehicle or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgement against the Borrower, the whole of the principal sums and which shall then be remaining due and unpaid under these presents and the Principal Deed shall forthwith become payable.

4. In pursuance of the said agreement and the consideration aforesaid the Borrower doth hereby declare that the motor vehicle described in the Schedule (to the Principal Deed and which is also described in the Schedule) hereunder shall be security for and charged with payment to the Government as well of the said sum of Rs. .... or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents secured under the said Principal Deed and the sum of Rs. .... according to the covenant in that behalf herein before contained and that the same shall not be redeemed to redeemable until payment of the moneys secured under this deed and the Principal deed.

5. And it is hereby agreed that all powers, provisions and covenants contained and implied in the aforesaid Principal Deed in relation to the money secured thereby shall operate and take effect in like manner or securing payment of the principal and to the security as fully as if the same had been herein set out and specifically made applicable thereto and as if the said sum had formed part of advance secured by the Principal Deed.

## THE SCHEDULE

Description of Motor Vehicle .....  
 Maker's name .....  
 No of Cylinders .....  
 Engine No .....  
 Cost Price .....

IN WITNESS WHEREOF the said ..... and ..... for and on behalf of the  
 President have hereunto set their respective hands the day and the year above written.

Signed by the said ..... in the presence of:  
 (name and designation of the borrower)

1. ....  
 2. ....

(Signature of witness)

(Signature and designation of the  
 Borrower)

Signed by ..... in the  
 (Name and designation of the President of India)

Presence of:

1. ....  
 2. ....

(Signature of witness)

(Signature and designation of the Officer  
 signing for and on behalf of the President  
 of India).

Note:— The Principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 4, dated 5th Jan 66 vide Government Notification, Ministry of Defence No. SRO 1-E dated 5th Jan 1966 and was subsequently amended by:—

- (i) Government Notification No. SRO-9-E dated 19 Mar 74 Published in the gazette of India, Part II Section 4 at page 1 to 124.

DIHRENDRA SINGH, Jt. Secy.